एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : आयाम एवं क्रियान्वयन"

27 मई, 2023 (शनिवार)

स्मारिका

मुख्य सम्पादक

डॉ0 प्रवेश कुमार मिश्र

सह सम्पादक

डॉ0 राजीव दूबे

सह सम्पादक

डॉ0 शिवेन्द्र सिंह चंदेल

आयोजक :

IQAC एवं बी0एड विभाग, राठ महाविद्यालय पैठाणी

पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

प्रायोजक :

राठ शिक्षा विकास समिति, पैठाणी पौड़ी गढ़वाल

उत्तराखण्ड।

मुख्य संरक्षक

श्री गणेश गोदियाल (संस्थापक राठ महाविद्यालय पैठाणी)

संरक्षक

श्री दौलत राम पोखरियाल

(प्रबन्धक राठ महाविद्यालय पैठाणी)

संगोष्ठी संयोजक

डॉ0 जितेन्द्र कुमार नेगी

प्राचार्य, राठ महाविद्यालय पैठाणी

सम्पादकीय

राठ महाविद्यालय पैठाणी द्वारा **''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : आयाम एव क्रियान्वयन''** विषय पर दिनांक 27 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय संगोष्ठी की स्मारिका आप सब के समक्ष प्रस्तुत करते हुये मुझे अन्त:करण से बहुत ही हर्ष हो रहा है। महाविद्यालय की स्थापना के पश्चात किसी राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन का यह द्वितीय प्रयास है।

भारतवर्ष लगभग 34 वर्षो के समयान्तराल के पश्चात् अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन कर रहा है। वैश्विक परिस्थितियों में तीव्र बदलाव के साथ ऐसे परिवर्तन आवश्यक हैं। वैश्विक स्तर पर शिक्षा में नित्य नये प्रयोग किये जा रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप प्राप्त प्रौद्यौगिकी का प्रयोग शिक्षा में प्राय: होता रहा है, जिससे सूचनाओं के नवीन द्वार खुले हैं। इण्टरनेट के प्रयोग ने सूचना प्राप्ति को सहज किया है, परन्तु इसके दुष्प्रभाव भी बढ़े हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रति युवाओं में रूचि की कमी दृष्टिगोचर हो रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा भारत सरकार तथा विद्वतजनों का प्रयास है कि भावी पीढ़ी विश्वस्तरीय ज्ञान के साथ भारतीय पुरातन ज्ञान, सभ्यता एवं संस्कृति को भी जाने।

चूंकि राठ महाविद्यालय एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित है, इसलिये संस्थान का दायित्व है कि नई शिक्षा नीति 2020 को जन-जन तक पहुंचाया जाय। महाविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी इसी दिशा में किया गया एक लघु प्रयास है।

इस संगोष्ठी में विषय विशेषज्ञों, शिक्षा अधिकारियों तथा सुविज्ञ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शोध पत्र की झलक, स्मारिका के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का एक प्रयास महाविद्यालय परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किया जा रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि महाविद्यालय परिवार के सदस्यों का संयुक्त प्रयास, स्मारिका को उत्कृष्ट बनाने तथा महाविद्यालय के संस्थापक **''श्री गणेश गोदियाल जी''** के **''मिशन उच्च शिक्षा''** को जन-जन तक पंहुचाने में सफल होगा। मै संपूर्ण राठ शिक्षा विकास समिति के साथ-साथ संस्था के सम्मानित प्रबन्धक श्री दौलत राम पोखरियाल एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ0 जितेन्द्र कुमार नेगी के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होने मुझे यह पुनीत अवसर प्रदान किया।

समस्त विद्धतजनों, प्रतिभागियों एवं महाविद्यालय परिवार के स्नेह, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा के साथ सभी को शुभकामनाऐं।

डॉ0 प्रवेश कुमार मिश्र
(आयोजन सचिव)

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)-246174, उत्तराखण्ड, भारत
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Garhwal)-246174 Uttarakhand, India
(A Central University)

प्रो0 अन्नपूर्णा नौटियाल
कुलपति

Prof. Annpurna Nautiyal
Vice-Chancellor

Ph. No. : 01346-250260
Fax No. : 01346-252174

Ref. No. : VC/HNBGU/2023/290
Dated : 17 / 05 / 2023

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि **राठ महाविद्यालय पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)** द्वारा ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 आयाम एवं क्रियान्वयन'' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।

वर्तमान में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लेकर देशभर में व्यापक चिंतन चल रहा है। ऐसे में महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन महत्वपूर्ण है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि विद्वान विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं तथा जिज्ञासू छात्र-छात्राओं द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 को समझने-जानने का पूर्ण अवसर मिलेगा

मेरी ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी की सफलता हेतु हार्दिक शुभकामनायें।

(अन्नपूर्णा नौटियाल)

प्राचार्य,
राठ महाविद्यालय, पैठाणी
पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड

हल्द्वानी - 263139 (नैनीताल)

Mail-Higherdocation.director@gmail.com

प्रो0 (डा0 सी0डी0 सूंठा)
निदेशक (उच्च शिक्षा)

अर्द्धशासकीय पत्रांक 741/2023-24
दिनांक 06 मई, 2023

संदेश

महोदय,

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्ता हुई कि राठ महा विद्यालय पैठाणी, जिला-पौड़ी गढ़वाल द्वारा ''**राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-आयाम एवं क्रियान्वयन**'' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी पर स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अन्य हितधारकों को 'नई शिक्षा नीति-2020' के अन्तर्गत विभिन्न आयामों पर चेतनाजागरण एवं प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से उत्तराखण्ड शासन की पहल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन तीव्र गति से प्रारंभ कर दिया गया है। ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020'' के द्वारा समाज में बदलाव लाने तथा भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाने के साथ-साथ छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने एवं संवैधानिक मूल्यों, देशप्रेम की भावना जागृत करने में सार्थक सिद्ध होगी।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त राष्ट्रीय संगोष्ठी इस दिशा में अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होगी। मैं स्मारिका के प्रकाशन हेतु अपनी शुभकामनाऐं प्रदान करता हूँ।

मंगलकामनाओं सहित।

प्राचार्य,
राठ महाविद्यालय, पैठाणी
पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

प्रो0 (डा0 सी0डी0 सूंठा)

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand)-246174
केन्द्रिय विश्वविद्यालय
(A Central University)

Ref. No.:HNBGU/ RO /2023/105 Date: 10/05/2023

संदेश

बहुत प्रसन्नता का विषय है कि राठ महाविद्यालय पैठाणी, जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारा ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020–आयाम एवं क्रियान्वयन'' विषय पर 27 मई, 2023 को एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि विभिन्न प्रान्तों के प्रतिभागी उक्त विषय की संगोष्ठी में प्रतिभाग करेंगे।

राठ महाविद्यालय पैठाणी के द्वारा शिक्षा से जुड़े हुए विषय पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन करना सराहनीय है। महाविद्यालय के द्वारा शिक्षा के विकास के लिए किये जा रहे प्रयास हर्षित करते है। इस संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए अग्रिम बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं।

पुनः शुभकामनाओं सहित सादर।

10.05.2023
प्रो० एन०एस० पंवार
कुलसचिव

प्राचार्य,
राठ महाविद्यालय, पैठाणी
पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

संदेश

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राठ महाविद्यालय पैठाणी एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन दिनांक 27 मई 2023 को **''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : आयाम एवं क्रियान्वयन''** विषय पर आयोजित कर रहा है।

राठ महाविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ही उच्च शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने का रहा है। राठ जैसे ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन एक सराहनीय प्रयास है। मेरी आशा है कि यह सेमिनार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सम्बन्ध में प्राध्यापकों, शोधार्थियों एवं छात्र/छात्राओं की जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने में उपयोगी सिद्ध होगा।

उक्त राष्ट्रीय सेमिनार के सफल आयोजन की कामनाओं के साथ समस्त महाविद्यालय परिवार को हार्दिक शुभकामनाऐं प्रेषित करता हूँ।

श्री गणेश गोदियाल

संस्थापक

राठ महाविद्यालय पैठाणी

पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

संदेश

हमारे लिये यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि राठ महाविद्यालय पैठाणी के IQAC एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत स्मारिका प्रकाशित होने जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: आयाम एवं क्रियान्वयन विषय पर आयोजित होने वाली संगोष्ठी एवं स्मारिका प्रकाशन के माध्यम से हम सबको इस विषय पर विशेषज्ञों, प्राध्यापकों एवं शोधार्थियों के विचार जानने का अवसर मिलेगा, जिससे सभी लाभान्वित होंगे।

मुझे आशा है कि हम अपने उद्देश्य पूर्ति में सफल होंगे। मैं आयोजन सचिव सहित सम्पूर्ण आयोजन टीम को स्मारिका प्रकाशन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाऐं प्रेषित करता हूँ।

प्राचार्य

राठ महाविद्यालय पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल

उत्तराखण्ड

संदेश

मेरे लिये यह बड़े हर्ष का विषय है कि राठ महाविद्यालय पैठाणी के IQAC एवं बी0एड0 विभाग द्वारा दिनांक 27 मई 2023 को **''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : आयाम एवं क्रियान्वयन''** विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजन किया जा रहा है और इसे चिरस्मरणीय बनाये रखने के लिये स्मारिका एवं संपादित पुस्तक का प्रकाशन भी किया जा रहा है। मेरा मानना है कि इस प्रकार की संगोष्ठी से न केवल शिक्षक एवं छात्र अपितु समाज का एक बड़ा हिस्सा भी लाभान्वित होता है, जिसका प्रभाव अन्ततः देश के विकास पर पड़ता है। मेरी शुभकामना है कि यह राष्ट्रीय संगोष्ठी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो। मै आशा करता हूँ, कि इस संगोष्ठी में विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शोध पत्र निश्चियतः भविष्य की योजनाओं के निर्माण में सहायक एवं मार्गदर्शक सिद्ध होंगे।

मेरी तरफ से IQAC एवं बी0एड0 विभाग तथा समस्त महाविद्यालय परिवार को कोटिशः शुभकामनायें।

प्रबन्धक

राठ महाविद्यालय पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल

उत्तराखण्ड

एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : आयाम एवं क्रियान्वयन"

27 मई, 2023 (शनिवार)

प्रमुख वक्ता (प्रथम सत्र)

(प्रो0 रमा मैखुरी) संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय हे0न0ब0ग0वि0वि0 श्रीनगर, गढ़वाल	**(प्रो0 दीपक पाण्डेय)** सहा0 निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रमुख वक्ता (द्वितीय सत्र)

(डॉ0 आनन्द भारद्वाज) मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल	**(प्रो0 अनूप के0 डोबरियाल)** डीन लाइफ साइंस, पूर्व निदेशक हे0न0ब0ग0वि0वि0 पौड़ी परिसर

(डॉ0 शिव कुमार भारद्वाज)
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

विषय

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : आयाम एवं क्रियान्वयन"

उप-विषय :-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: विश्लेषण एवं क्रियान्वयन
2. कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा
3. शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग एवं नवाचार
4. भारतीय बौद्धिक सम्पदा एवं आधुनिक भारत
5. प्राचीन भारतीय योग पद्धति
6. बहुविषयक शिक्षा के विविध आयाम
7. नई शिक्षा नीति 2020 के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव
8. स्कूली शिक्षा में परिवर्तन एवं क्रियान्वयन
9. उच्च शिक्षा में परिवर्तन एवं क्रियान्वयन
10. प्राचीन शिक्षा पद्धति एवं उसकी प्रासंगिकता
11. भारतीय भाषाओं का संवर्धन एवं संरक्षण
12. कला और संस्कृति का संवर्धन एवं संरक्षण

संगोष्ठी के विषय में

किसी भी राष्ट्र का विकास वहां प्रचलित शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है, जिसके माध्यम से हम समाज का नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करते हैं। भारतवर्ष कभी विश्वगुरू की संज्ञा से सुशोभित रहा, जिसके पीछे हमारी शिक्षा व्यवस्था ही रही है। विश्व के अनेक देशों के विद्यार्थियों के लिये भारतीय शिक्षा आकर्षण का केन्द्र रही है। भारतवर्ष में तक्षशिला एवं नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय आकर्षण का केन्द्र रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने ऐसे सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओं का संचालन किया जिससे प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार उपलब्ध रहा। मुगल कालीन नीतियों और ब्रिटिश शासन की नीतियों ने हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार किया जिसके दुष्परिणाम से हम अद्यतन निकल नही सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप भारत सरकार द्वारा 1968, 1986 तथा 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से शिक्षा को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया गया। नई शिक्षा नीति 2020, जो लगभग 34 वर्षों के अन्तराल के बाद भारत सरकार द्वारा लाई गयी जिसके अन्तर्गत शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि सरकार की इस नीति को वास्तविक धरातल तक पहुंचाने तथा फलीभूत करने का सशक्त माध्यम अध्यापक वर्ग है। अध्यापक ही इस नीति की सफलता को तय करेगा। जितना बेहतर अध्यापक वर्ग नीति की मंशा को समझ पायेगा तदनुरूप ही नीति फलीभूत होगी। राठ महाविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में स्थापित है। इस संगोष्ठी के आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जन-जन तक पहुंचाना तथा फलीभूत करना है।

राठ महाविद्यालय : एक संक्षिप्त परिचय

उत्तराखण्ड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में विकासखण्ड थैलीसैंण के पैठाणी कस्बे में जिला मुख्यालय पौड़ी से लगभग 50 (पचास) किमी0 पूर्व पश्चिमी नयार नदी के तट पर स्थित राठ महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 2003 में की गयी।

जनपद का यह भू-भाग विकास से कोसों दूर अशिक्षा और पिछड़ेपन से पीड़ित रहा है। आजादी के बाद भी यह क्षेत्र शिक्षा के अभाव में अनेक तरह की विषमताओं से घिरा रहा। यद्यपि शुरुआती दौर में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रारम्भिक प्रगति ने जरूर कुछ विसंगतियों को समाप्त किया, परन्तु उच्च शिक्षा प्राप्त करना यहाँ के युवाओं का स्वप्न मात्र ही बना रहा। इस अभाव और वेदना को महसूस करते हुए इसी क्षेत्र के ग्राम बहेड़ी के युवा श्री गणेश गोदियाल जो सुदूर मुम्बई में एक स्थापित व्यवसायी के रूप में क्रियाशील थे, ने क्षेत्र के तमाम संभ्रान्तजनों, जागरुक नागरिकों व जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क व सहयोग स्थापित कर ग्राम सभा पैठाणी के दानवीरों द्वारा दान की गई भूमि पर इस महाविद्यालय को आकार देना सुनिश्चित किया।

जुलाई 2003 में महज 30 छात्र-छात्राओं, प्राचार्य, सात प्राध्यापकों व 18 शिक्षणेत्तर कर्मियों के साथ यह "**मिशन उच्च शिक्षा**" प्रारम्भ हुआ, जो आगे चलकर क्रमशः नये कीर्तिमान गढ़ता चला गया।

26 मार्च 2015 को श्री गणेश गोदियाल (तत्कालीन विधानसभा सदस्य, उत्तराखण्ड) के निजी प्रयासों से इस महाविद्यालय को राज्य सरकार की अनुदानित श्रेणी में लाया गया है। वर्तमान समय में महाविद्यालय में बी0ए0, बी0एड0 एवं बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिसमें लगभग 750 छात्र-छात्राऐं अध्ययनरत हैं।

पैठाणी : एक परिचय

पौडी गढ़वाल जनपद के कोटद्वार (गढ़वाल का प्रवेश द्वार) से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित पैठाणी (थैलीसैण ब्लाक) उत्तराखण्ड के मानचित्र में एक छाटे से गाँव के रूप में अंकित है। लेकिन यह एक छोटा सा गाँव राजनीतिक, धार्मिक एवं शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

उत्तराखण्ड में पर्यटन की दृष्टि से पैठाणी के महत्व को किसी भी अन्य स्थान से कमतर नही आंका नही जा सकता। पैठाणी एक पौराणिक गाँव है क्योकि इसका उल्लेख स्कन्दपुराण के केदारखण्ड में दर्ज है और दर्ज है इससे जुडे कई रोचक प्रसंग। केदारखण्ड के अनुसार राष्टकूट पर्वत पर भगवान शिव ने कठोर तप किया था। केदारखण्ड में कहा गया है **''ऊँ भूर्भव स्वः राठीनापुरोहव पैठीन सिग्रोत्र राठो इहागेच्छिति।''** अर्थात् राहू के गोत्र पैठीनली के कारण इस गाँव का नाम पैठाणी पड़ा। राहू के अद्भुत मंदिर एवं राष्टकूट पर्वत के कारण यह पूरा क्षेत्र राठ क्षेत्र कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार पैठाणी स्थित प्रसिद्ध मन्दिर का निर्माण आठवीं शप्ताब्दी ईस्वी में आदि शंकराचार्य द्वारा करवाया गया। वर्तमान समय में इस मन्दिर की देख-भाल बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा की जाती है।

सलाहकार समिति

1. प्रो0 नारायण सिंह राव, इतिहास विभाग, हिमाचल केन्द्रिय विश्वविद्यालय, शिमला
2. प्रो0 प्रदीप कुमार शर्मा, हिन्दी विभाग, सिक्किम केन्द्रिय विश्वविद्यालय गंगटोक, सिक्किम
3. प्रो0 के0सी0 पुरोहित, पूर्व निदेशक, हे0न0ब0ग0वि0वि0 पौड़ी कैम्पस
4. प्रो0 आर0 एस0 नेगी, पूर्व निदेशक, हे0न0ब0ग0वि0वि0 पौड़ी कैम्पस
5. प्रो0 एम0 एम0 सेमवाल, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, हे0न0ब0ग0वि0वि0 श्रीनगर, गढ़वाल
6. प्रो0 अजय दूबे, शिक्षा संकायाध्यक्ष, वीर बहादुर सिंह पू0वि0वि0 जौनपुर (उ0प्र0)
7. प्रो0 रवि शरण दीक्षित, इतिहास विभाग, डी0ए0वी0 पी0जी0 कॉलेज, देहरादून

आयोजन समिति

1. **पंजीकरण समिति** – डॉ0 बीरेन्द्र चन्द, डॉ0 मनजीत सिंह भण्डारी
2. **स्वागत समिति** – डॉ0 लक्ष्मी नौटियाल, डॉ0 दुर्गेश नन्दिनी
3. **प्रकाशन समिति** – डॉ0 शिवेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ0 राजीव दूबे
4. **सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति** – श्री प्रदीप कुमार, डॉ0 राकेश कुमार
5. **अनुशासन समिति** – श्री उमेश चन्द्र बंसल, श्री राहुल सिंह
6. **मंच समिति** – डॉ0 देव कृष्ण, श्रीमती बन्दना सिंह
7. **विशिष्ट अतिथि व्यवस्था** – डॉ0 मनोज सिंह, डॉ0 रवि
8. **जलपान/भोजन व्यवस्था समिति** – श्री राजकुमार पाल, श्री संदीप लिंगवाल

Challenges in the Implementation of the National Education Policy 2020: A Sociological Evaluation

Dr Satyam Dwivedi
Associate Professor
Department of Sociology
DAV (PG) College, Dehradun-24800, Uttarakhand (India)
E-Mail ID: drsatyamdwivedi@gmail.com

ABSTRACT: To compete to the world in global scenario many reforms have been done so far in education in India because we believe that merely educating peoples of the country cannot achieve the goals of a developed nation. The education should inculcate the true values to maintain the human dignity for unity and integrity of the nation. India has a glorious history of education since ancient times and we are always reforming our education so that we can contribute to the world of global development as a nation. Recently we have opted the new education policy 2020 in place of the old education policy 1986 for making India a global knowledgeable nation which focuses on achieving full human potential and developing an equitable society for promoting national development. The reforms through new education policy are to make an equilibrium between the modern knowledge and the rich Indian heritage and to achieve the highest human goals so that we can follow the concept of 'Vasudhaiv Kutumbakam' and lead to the path of glory not only for our country but for the whole world. The present paper focuses on the challenges in implementation of the New Education Policy 2020 in sociological perspective.

Keywords: New Education Policy 2020, Social and Human Values, Equitable Society, Development.

Design of Skill Development Modules for Students of Pharmaceutical Education in India

Dr. Somesh Thapliyal
Assistant Professor
Department of Pharmaceutical Sciences
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
(A Central University)
Srinagar Garhwal, Uttarakhand
Email: somesh.thapliyal@gmail.com
Somesh.thapliyal1979@hnbgu.ac.in
ORCID ID: https://orcid.org/0009-009-5083-324X
Mob: 09411076094, 7060833734

ABSTRACT: The pharmaceutical industry is growing rapidly. It is predicted that there will be a great need for skilled workers in the coming decades. However, the skilled workforce in the pharmaceutical industry is extremely limited. Skills development is important in terms of demand and supply. In most pharmaceutical colleges and universities, students study outdated curriculum and there is less industrial experience or hands-on training needed for the skill development needed to meet industry demand. A competence development module needs to be developed that can be integrated into an educational program. This article focuses on the development of modules for pharmacy students, curriculum design, training school, and the introduction of various strategies and teaching techniques to develop pharmacy student skills.

Holistic and Multidisciplinary Education: Core Element of NEP 2020

Dr Peeyush Misra
Associate Professor
Department of Statistics
DAV (PG) College, Dehradun-248001
Uttarakhand (India)
E-Mail ID: dr.pmisra_dav@yahoo.com

ABSTRACT: As we know that the education is like an important pivot in the development of individual and society both so it is our responsibility to incorporate innovation and new trends in education and keep changing education policies from time to time. So in this sequence, the new education policy 2020 was brought. We strongly believe that due to this new education policy, there will be a new twist in the form of education and teaching methods of our country which will boost our new minds to compete to the world in global scenario. The new education policy focuses not only in educating peoples of the country but also on inculcating the true values to maintain the human dignity for unity and integrity of the nation and this will definitely help in making India a global knowledgeable nation and establishing an equilibrium between the modern knowledge and the rich Indian heritage of the highest human goals. The main aim of the New Education Policy 2020 is to provide holistic and multidisciplinary education to all so that they can participate in the development of the nation in all the ways.

Keywords: Holistic and Multidisciplinary Education, Education Policy 2020, Human Values, and Development.

Social And Economical Effect Of New Education Policy 2020

Dr. Akhilesh Kumar Singh
Assistant Professor
Department Of B.Ed.
Raath Mahavidyalaya Paithani
Pauri Garhwal, Uttarakhand

ABSTRACT : NEP is the first education policy of 21st century .During the COVID-19, the only positive that happened in the field of education in India was this policy which promises to transform the education system of India. As they say, change in the law of nature but this change was overdue for more than 35 years .The last time we saw a similar change in the field of education was back in the year 1986. For anything to survive in this dynamic world it is important to adapt to the changing scenario. Same goes for education, with changing information and communication technology (ICT), industrial requirement, there is need for change in the way we learn .And as the global scenario in education has been changing rapidly witnessing a paradigm shift in the overall system .It was important for India also to catch up with that change, an effort in this direction has been made through NEP 2020 to reform the education system in India.

Higher educational institutions (HEIs) can play an important role to achieve the objectives of socio-economic development of New India through their active community engagement. This approach will also contribute to improvements in quality of both teaching and research in HEIs as they will develop better understanding of issues confronting the society.

Implementation Strategies of Higher Education Part of National Education Policy 2020 of India towards Achieving its Objectives

Dr. Manjeet Singh Bhandari
(Assistant Professor)
Department of Physical Education
Raath Mahavidyalaya Paithani
Pauri Garhwal Uttarakhand
Cont. No. 8200108789, 9979205677
E-mail : manjeetsport1610@gmail.com

ABSTRACT

Well defined and futuristic education policy is essential for a country at school and college levels due to the reason that education leads to economic and social progress. India with the leadership of its current prime minister and an expert team with members of varied backgrounds has developed and planned to implement a new education policy during the next decade of the 21st century called Indian National Education Policy (NEP-2020). The aim, objectives, and details are well known to practitioners and the public. NEP-2020 is an innovative and futuristic proposal with both positive and negative aspects, framed with the objective to provide a quality school education and higher education to everyone with an expectation of holistic & research-oriented progress. This paper initially depicts an overview of NEP-2020, distinguish the strengths & weakness of the policy at higher education & research part, evaluation of the implementation suggestions given in the policy, identifying and analyzing possible generic strategies for implementation of NEP-2020 to fulfill its objectives based on focus group discussions. The paper also includes many predictive proposals on issues like developing quality universities & colleges, institutional restructuring & consolidation, more holistic & multidisciplinary education, optimal learning environment & student support, transforming the regulatory system of higher education, technology usage & integration, and online & digital education. Finally, some recommendations are made to implement the NEP- 2020 effectively irrespective of various constraints. This article can be considered as a reference to the policy implementation teams of Govt of India.

Keywords : NEP 2020, Indian Higher Education Policy, Implementation Strategies, Indian Higher Education System, Research and innovation focus.

NEW EDUCATION POLICY 2020 AN IMPLEMENTATIONS
Change and implementation in Higher Education

Reena Purohit*
Department Of Chemistry,
Bal Ganga Degree College Sandule Kemar.
Shri. Dev Suman University Uttarakhand
Reenapurohit208@Gmail.Com
Mobile No-8979886799

ABSTRACT

Change and implementation in Higher Education, Sometimes the school year doesn't go quite as planned. On those occasions when schools must be closed due to bad weather or other circumstances, many institutions, collages and districts shift to e- Learning. A virtual classroom environment can help students maintain the momentum of learning while they are unable to be physically present. This momentum can make the transition back into the classroom easier for students and teachers alike. Due to covid 19 pandemic necessity of teaching & learning tools have been increased and his time is implementations of new strategies in pedagogy and technology development has made the online education highly comfortable. The paper entitled different type of learning tools used in teaching learning and challenges of online learning for students and teachers and how to overcome Fortunately, there are great deal of resources available to make online learning interesting. We have compiled a list of resources covering a diversification of subjects, from art to science and much more. Educator and parents can use these resources to uplift virtual classroom time as well as keep students engaged in learning for better change and implementation in higher education.

KEY WORD-: Online Resource, Learning, virtual Classroom.

NEP 2020: Beyond the Boundaries

Dr. Manoj Kumar Sharma
Assistant Professor
K.L.D.A.V. (P.G.) College, Roorkee
Distt- Haridwar, PIN- 247667, Uttarakhand
Mob. 9871015952
Email : medmanoj@gmail.com

ABSTRACT

As the National Education Policy 2020 launched and implementation process has already started at different levels of education by the state and centre. It is the policy where government is also focussing a lot on its proper implementation and trying to strengthen the base of education at every level so that it can executed properly. In India, the education system was at its highest peak when we were considered as 'Vishawa Guru' but we lost our glory in the middle and drained everything. It is quite impactful this policy is in terms of bringing major changes in our education system. There were no boundaries in our ancient education system, and we were getting education of different disciplines under one umbrella. The National Education Policy 2020 is going to give the same environment beyond the boundaries of different disciplines. We are giving importance to the degrees for taking a job which

might somewhere hinder the real talent of the individual. It should be skill which must be given the primary importance to achieve the real-life goal. In many policies, commissions, and reports it has been focussed to develop the skills trough vocational education but very least importance is given towards the skill development. The National Education Policy 2020 is not just highlighting the skill development but will also help in overall personality development of the individual and support for better adjustment in their personal, professional, and academic adjustment.

Key Words : National Education Policy-2020, Disciplines, Skills, Boundaries.

In view of New Education Policy The Implementation of ICT in Library & Information Science

Magan Singh Bhandari
Assistant Librarian
RMV Paithani
Pauri Garhwal (U.K.)

ABSTRACT

In view of New Education Policy -2020 the modern libraries must be implemented information communication technology so as to make digitized and must be in automation mode, fully equipped with high technological instruments. So as to follow NEP-2020 in libraries, well designed databases are managed. Library automation software must be implemented for automation of libraries to perform all housekeeping works. Library and information services e.g. altering service, bibliographic full text services, document delivery services, reference services etc. must be in regular basis. Libraries must have high speed internet and facilitated with wi-fi facilities. A peaceful and reading and learning environment must be created in modern libraries through different efforts. Hence Libraries must be facilitated with modern technological development and new inventions, so as to meet with new challenges and to play a leading role as a backbone of Institution. Libraries must be updated time to time and workshops, seminars, webinars, conferences and training programs must be organized with help of specialists and experts. Users satisfaction is the main of Libraries and for this purpose user study is necessary. To study about users we must know attitude of users . If we know attitude of user towards library and information science services we can sassily study about users. In this way can know about need and satisfaction of users. Hence we will be able to form a library according to the needs and expectancy of users.

National Education Policy-2020 Towards a Quality Higher Education Ecosystem

Jai Singh Yadav
Assistant Professor
Department of B.Ed.
Kashi Naresh Government P.G. College
Gyanpur Bhadohi

ABSTRACT

Quality higher education ecosystem is fundamental for transformation of any nation. National Education Policy-2020 deeply observed the Indian higher education system and find that it is fragmented. It is suffering early specialisation . It has also less access disadvantage areas. The Policy

envisions a complete transformation of our higher education system to minimise .This policy recommends for large multidisciplinary universities and colleges,with at least one or near every districts , revamping curriculum,science of teaching and learning,assessment ,merit appointments, flexible degree programme with multiple exit options for students etc. It also recommends to establish some new structures for quality higher education system. Multidisciplinary Education and Research Universities(MERUs) for achieving international standards, Higher Education Commission of India (HECI) for transformation of regulatory system, National Research Foundation (NRF) for quality research ecosystem etc. Thus this policy leads for transformation of higher education ecosystem for quality concerns.

Keywords: National Education Policy-2020, higher education ecosystem, MERUs, HECI.

Analysis Of The Indian NEP2020 Towards Higher Education

Dr Santeshwar kumar Mishra
Assistant Professor Department of Sociology
Nehru Gram Bharati Deemed To Be University
Prayagraj (U.P.)

ABSTRACT

Higher Education plays a crucial role by serving a base for understanding covil and aocial rights. Implementation of a policy ensures that. Successfully implementing NEP 2020 guidelines and ensuring educational standards in India. The NEP implemented in 2020 has a huge impact on the country's higher education and its sufficient to say that it revolutionised the course of school education towards a brighter future. The much needed changes were put in place to tackle the growing problems in the education sector. After the Covid situation slowly became normalised the New Education Policy brought back education to normal. The immediate effects of NEP 2020 were on point and managed to provide a much needed push to the education system. NEP 2020 was put in place in 2020 to address a lot of problems which rose in the education sector in the last decade.

National Education Policy 2020 Promoting Girls Education in Slum: A Sociological Study.

Kadambinee Research Scholar
Department of Sociology
T.D P.G College
Jaunpur

ABSTRACT

The National Education Policy (NEP) 2020 is a comprehensive initiative aimed at transforming the education sector in India. The policy has provisions that aim to promote girls' education in India, including in slums. Slums are densely populated areas characterized by poor living conditions, inadequate infrastructure, and limited access to basic services such as education. This research paper examines the NEP 2020's provisions for promoting girls' education in slums in India and its potential impact on gender equity and inclusion. It draws on existing literature and discusses the role of socio-economic factors in limiting girls' access to education. The paper concludes that the NEP 2020's provisions for promoting girls' education in slums represent a significant step forward in promoting

gender equity and inclusion in education in India. However, the success of the policy will depend on its effective implementation, and the paper highlights the need for continued efforts to improve girls' access to education in slums and address the broader socio-economic factors that limit their opportunities. Overall, this research paper contributes to the growing body of literature on girls' education in India and the role National Education Policy (NEP) 2020 in promoting gender equity and inclusion in education.

Keywords : NEP, Slum, Girls, Education, Gender, Inclusion.

Opinion of KV Female and JNV Female Teachers of Physical Education towards IT in India.

Dr. Krishna Kumar Pandey
Assistant Professor,
Major Dhyanchand Institute of Physical Education,
Bundelkhand University, Jhansi, U.P., India
E-mail: pandeykk13@gmail.com, +918299584411

ABSTRACT

The resolution of the study was to evaluate the Kendriya Vidyalaya female and Jawahar Navodaya Vidyalaya female Physical Education teacher's opinion towards Information Technology. For this study total Seventy (70) Physical Education teachers retract as a subject. From Kendriya Vidyalaya Twenty-Three (23) Physical Education female teacher's and Jawahar Navodaya Vidyalaya Forty-Seven (47) Physical Education female teachers selected as a subject. The teachers who were teaching or coaching Physical Education in different schools were delimited for this study. Faculty Opinion towards Information Technology (FAIT), a 67 item opinion scale elevated by Elizabeth Libby Gilmore (1998), was used to know the opinion of teacher's towards Information Technology. The reply acquired from physical education female teachers of different central government schools were changed into simple percentage for the purpose of investigation and interpretation of the data. To analyses the collected data 't' test was used to compare opinion of Kendriya Vidyalaya and Jawahar Navodaya Vidyalaya Physical Education female teachers towards information technology. Statistical investigation were implemented using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 19, a product of IBM.nic in order to compare all the above. The level of significance was set at .05. The study exposes that, there is no significant difference between Kendriya Vidyalaya and Jawahar Navodaya Vidyalaya Physical Education female teachers from different central government education schools in India towards information technology.

Keywords : Kendriya Vidyalaya; Jawahar Navodaya Vidyalaya; Physical Education; Teachers; Opinion; Information Technology.

Digital Education Through the Lens of NEP 2020

Dr Durgesh Nandini
Assistant Prof. B.Ed.
Raath Mahavidyalaya Paithani
Pauri Garhwal, Uttarakhand

ABSTRACT

Our Prime Minister once said, “I dream of a digital India where quality education reaches the most inaccessible corners driven by digital learning.” There is no doubt that the NEP Policy 2020 is a holistic attempt to turn his dream into a reality.

The National Education Policy (NEP) 2020, implemented by the Government of India, aims to transform the education system by addressing various challenges and leveraging digital technologies. This research paper provides an in-depth analysis of the role of digital education in the context of the NEP 2020. It explores the key features of the NEP 2020 related to digital education, examines the benefits and challenges of implementing digital education, and discusses the implications for educators, students, and other stakeholders. Additionally, the paper highlights the necessary infrastructure, policies, and strategies required for the successful integration of digital education in Indian schools and universities. By examining the NEP 2020 through the lens of digital education, this research paper offers valuable insights and recommendations for policymakers, educators, and researchers involved in the advancement of education in India.

'भारतीय धर्म एवं साहित्य में पर्यावरण बोध'

डॉ0 विवेकानन्द चौबे,
असि0प्रो0 (प्राचीन
इतिहास एवं संस्कृति विभाग)
राष्ट्रीय पी0जी0 कॉलेज, जमुहाई, जौनपुर

मनुष्य की यह प्रवृत्ति रही है कि वह सदैव से स्वयं को प्रकृति का मात्र उपभोक्ता माना है। सम्भवतः इसी कारण वह यह तथ्य भूल जाता है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार असिमित नही हैं अतः उन्हें इसका दोहन सोच–समझकर करना चाहिये। उल्लेखनीय है कि हमारे प्राचीन ऋषि–मुनियों ने पर्यावरण के महत्व को समझकर ही उपवन लगाने और यज्ञ इत्यादि के सम्पादन का विधान किया था। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों के संतुलन के लिये सदैव प्रार्थना किया। वैदिक ऋषियों ने शुद्व एवं समृद्व पर्यावरण को मानव जीवन के विकास के लिये अनिवार्य ही नही बताया वरन प्रकृति की छोटी– बड़ी सभी शक्तियों को पूज्य और स्वयं को उपासक के रूप में माना है।

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में हमारे चारो ओर जो भी वस्तुयें विद्यमान हैं वे मानवीय क्रिया–कलापों को प्रभावित करती हैं और उनके अस्तित्व की सुरक्षा के लिये आवरण का निर्माण करती है। घने वन शुद्व एवं समृद्व पर्यावरण की पहचान होते हैं, इसलिये अथर्ववेद में कहा गया है कि जिस भूमि में वृक्ष एवं वनस्पतियां सदा विद्यमान रहती हैं वह भूमि समस्त जनों के भरण–पोषण में समर्थ होती है। पर्यावरण के प्रमुख घटक वनस्पति संरक्षण का प्राचीन दृष्टिकोण आज भी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि मेलाटोनिक नामक हार्मोन केला, बरगद एवं पीपल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।

शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग एवं नवाचार

1. रूपिन कुमारी
असिस्टेंट प्रो0 बी0एड0
मो0 : 9557592988, E-Mail- Rupinkandari90@gmail.com
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली)।

2. सीमा यादव
श्रीमती राजदेई देवी इ0का0, खुनियांव,
सिद्धार्थनगर (उ0प्र0)

शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षाहीन व्यक्ति पशुवत आचरण करता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, कि **शिक्षा विहिनः पशुभिः समानः** अर्थात शिक्षा से हीन व्यक्ति पशु के समान है यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि **विद्या ददाति विनयम्,** विद्या ही इन्सान को विनयशील बनाती है। शिक्षा ही व्यक्ति में संस्कार देती है और शिक्षा ही व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाकर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाती है। शिक्षित व्यक्ति नीर–क्षीर विवेकी होता है अर्थात उसे सही और गलत की पहचान होती है। वैदिक काल में विद्यार्थियों के मूल्यांकन का आधार शास्त्रार्थ होता था, चूंकि उस समय प्रमाण–पत्र प्रदान करने की व्यवस्था नही थी, इसलिए शास्त्रार्थ को महत्व दिया जाता था। स्वत्रंता के बाद कई समितियों तथा आयोंगों का गठन किया गया, जिनके द्वारा शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट/प्रतिवेदन भारत सरकार को समय–समय पर प्रस्तुत किये, जिनमें राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, नई शिक्षा नीति 1986 के बाद फिर नई शिक्षा नीति 2020 है।

वास्तव में भारत सरकार तथा देशवासियों को मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय साधन जुटाने होंगे, जिससे शिक्षा का सार्वजनीकरण साक्षरता हेतु रूचि तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। उपरोक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा को राष्ट्रीय विकास पुनरूत्थान के लिए पूँजी लगाने हेतु एक आवश्यक क्षेत्र माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में यह बतलाया गया है कि शिक्षा पर होने वाले निवेश को धीरे–धीरे बढ़ाया जाए, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके। इस शिक्षानीति में पाठ्यक्रम के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। केन्द्र सरकार का मानना था कि इस नीति को लागू करने के बाद देश में शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में परीक्षा प्रणाली को वैध एवं विश्वसनीय बनाने पर जोर

दिया गया था। इसके त्रिभाषा सूत्र को लागू करने पर जोर दिया गया था। इस शिक्षा नीति में अनुसंधान एवं विज्ञान शिक्षा एवं नवाचार को महत्व दिया गया, जिससे शिक्षा में उन्नयन हो सके, इसके अतिरिक्त नयी शिक्षा नीति 1986 का गठन किया गया। वर्तमान में वर्ष 2020 से पुनः नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में लागू की गयी, जिसके तहत् विद्यार्थियों का कौशल विकास पर भी जोर दिया जायेगा। कौशल विकास के अन्तर्गत विद्यार्थी की अभिक्षता, रूचि के आधार पर निर्भर करेगा किस क्षेत्र में अपने भविष्य को दिशा दे सकेगा। जिसमें कि शिक्षा ग्रहण करते–करते अपनी कार्यक्षमता में रूचि के साथ–साथ भविष्य के लिए अपने आपको तैयार करना सिखाया जायेगा।

महत्वपूर्ण शब्द :– नवाचार, शिक्षा, तकनीकी, निवेश, नीति, विहिन, ददाति, शास्त्रार्थ, पूँजी।

प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रासंगिकता: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में

डॉ0 शिवेन्द्र सिह चन्देल
असि0 प्रो0 बी0एड0 विभाग
राठ महाविद्यालय पैठाणी (पौड़ी गढ़वाल)

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी देश की सभ्यता व संस्कृति की पहचान कराती है। प्राचीन समय मे भारत को जो गौरव प्राप्त था उसका श्रेय हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को ही जाता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की विशिष्टता के कारण ही भारत ने सदियों तक न केवल विश्व का प्रतिनिधित्व किया अपितु विभिन्न उद्योग–धन्धों, कला–कौशल के क्षेत्र मे भी अग्रणी रहा। परन्तु वर्तमान समय की शिक्षा पद्धति स्कूल तथा विश्वविद्यालयी या रोजगार परक शिक्षा तक सीमित हो गयी है। यह बालकों का नैतिक या आध्यात्मिक विकास करने मे सफल नही है। आज समाज में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि हम अपने अतीत को जाने, अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति को अपनायें और गुरूकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं को आत्मसात करें, जिससे हम पुनः विश्व पटल पर अपनी पुरानी ख्याति को प्राप्त कर सके।

नई शिक्षा नीति 2020 प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान परम्परा को ध्यान मे रखकर तैयार की गयी है। इसका लक्ष्य भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के साथ–साथ बालक के रचनात्मक क्षमताओ का विकास करना है। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता को देखते हुए भारत सरकार ने ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'' मे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के प्रति विश्वास करते हुए इसके महत्व को स्वीकार किया है, जिसके द्वारा भारत पुनः अपनी खोई हुई ख्याति को प्राप्त कर सकता है।

नई शिक्षा नीति–2020 में नैतिक व मानवीय मूल्यों का समावेश

डॉ0 देव कृष्ण थपलियाल
राजनीति विज्ञान विभाग
राठ महाविद्यालय पैंठाणी (पौडी गढवाल)

शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति के भीतर सुषुप्त पडी विलक्षण क्षमताओ का विकास करना है। जिससे उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके, एक स्वस्थ और जागृत समाज के निर्माण के साथ पूर्ण विकसित राष्ट्र के निर्माण में भी उसका सहयोग प्राप्त हो सके। इसके लिए जरूरी है, कि शिक्षा में उन मूल तत्वों का समावेश हो, जो व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक व वैचारिक उच्चता को मजबूती प्रदान कर सके। भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है। और इन युवाओं को उच्चत्तर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध करानें पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा।

शिक्षा से चरित्र निर्माण होंना चाहिए शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करूणा और संवेदनशीलता विकसित करनीं चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है।

शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करें इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, और मूल्य का अवश्य समावेश किया जाये।

प्राचीन भारत और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्व परम्परा के आलोक में यह 'नीति' तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा ओर सत्य की खोज को भारतीय परम्परा और दर्शन में सदा सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और बल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व–स्तरीय संस्थानों नें अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किये थे ।

शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करें इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, और मूल्य का अवश्य समावेश किया जाये।

इस युग में ज्ञान के नये–नये परिदृश्य उभरनें के कारण पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनिकी विकास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करनें लगेंगी ओर दूसरी ओंर डेटा साइंस कंम्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मॉग बढेगी, जो विज्ञान, समाज विज्ञान, और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों।

रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया कि बच्चे को जो कुछ सिखाया जा रहा है। उसे तो सीखें ही और साथ ही वे सतत सीखते रहनें की कला भी सीखें, समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर्सबन्धों को देख पायें, कुछ नया सोच पायें और नयी जानकारी को नए ओंर बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पायें।

शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्क संगत विचार और कार्य करनें में सक्षम हो, जिसमें करूणा और सहानुभूति, साहस, और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य ओर आधार हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोंगों को तैयार करना है, जो कि अपनें संविधान द्वारा परिकल्पित–समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करे।

नई शिक्षा नीति–2020 के आलोक बनें पाठ्यक्रमों में जहॉ बेहतर व्यवसायी निर्मित होंगें वहीं प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य 'अच्छे इंसानों' के निर्माण की परिकल्पना भी साकार होगी।

वैदिक यज्ञ और उनकी वैज्ञानिकता : एक अवलोकन

डॉ0 राजीव दूबे
असि0 प्रो0 (इतिहास)
राठ महाविद्यालय पैंठाणी (पौड़ी गढ़वाल)

यज्ञ एक प्रकार का कर्मकाण्ड होता है, जिससे मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है अथवा ऐसी संभावना रहती है। यज्ञों का उल्लेख वैदिक सहित्य में मिलता है। वेद विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिये यज्ञों का विधान करते हैं। ध्यातब्य कि पूर्व मिमांसक भी यज्ञों को इच्छा पूर्ति का साधन मानते हैं लेकिन इस संदर्भ में किसी ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। इसके विपरीत ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के लिये यज्ञ का विधान किया गया है।

यजुर्वेद एक ऐसा वेद है, जिसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय वैसे यज्ञ हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति सम्भव थी। यज्ञ में पुरोहितों की भूमिका महतवपूर्ण थी । यज्ञों से सम्बन्धित सभी कार्यो के सम्पादन का दायित्व परोहितों का होता था। उनकी भूमिका के कारण उनको ऋत्वज, होत्र, उद्गाता इत्यादि कहा जाता था। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यज्ञों मे पुरोहितों का वर्चस्व था । सम्भवतः इसी आधार पर कालान्तर में पुरोहितों के अनेक संगठन बने जिनका मूल ऋग्वेद मे देखा जा सकता है

ऐसा लगता है कि ऋग्वैदिक काल के पश्चात जनसंख्या में वृद्धि के कारण नयी–नयी बस्तियां अस्तित्व में आयीं तब उससे उत्पन्न अव्यवस्था को नियंत्रित्र करने के क्रम में सेना एवं शासक के महत्व में वृद्धि हुयी तथा पुरोहितों की आर्थिक दशा प्रभावित हुयी। तब पुरोहितों ने यज्ञ के सम्पादन का कार्य अपने हाथों में ले लिया। लम्बे समय तक चलने वाले खर्चीले यज्ञों से पुरोहितों की आय में वृद्धि हुयी। यजुर्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में पुरोहितों के लिये दक्षिणा की बात कही गयी है। इसका आधार यह था कि यज्ञ से यजमान को होने वाले लाभ में पुरोहित हिस्सेदार नही होता था। इसके बदले में वह अपना पारिश्रमिक प्राप्त करता था।

यज्ञ का अर्थ यज्ञीय अग्नि में बलि देना तथा आहुति अर्पित करना बताया जाता है। यज्ञ शब्द संस्कृत के 'यन' धातु में नृ प्रत्यय लगाकर बना है। यज्ञ अथवा यज का अर्थ होता है, 'देव पूजा संगतिकरणा दानेशु'। वैदिक यज्ञ प्रतीक है कि वैज्ञानिक दृष्टि से सहयोगी या विरोधी जो भी सामग्री आहुति में डालते हैं अग्नि में उनके मालीक्यूल टूट कर एक हो जाते हैं। यह इस बात का प्रमाणीकरण है कि प्रकृति में दृश्यमान विभिन्नता वास्तव में एक प्रकार की एकता है।

प्रमुख शब्द :– कर्मकाण्ड, प्रतिपाद्य, संगतिकरणा, मालीक्यूल।

प्राचीन शिक्षा पद्धति एवं उसकी प्रासंगिकता

डॉ0 मनोज कुमार सिंह
असo प्रोo (बी.एड.)
राठ महाविद्यालय पैंठाणी (पौड़ी गढवाल)
मोo : 9450589250, 8423407334
ई–मेल : mksingh20111@gmail.com

सारांश

वैदिक शिक्षा को हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा माना जाता है। इसका रोजगार के अवसरों से कोई लेना–देना नहीं है। यह बहुत अच्छा होगा अगर हम इसे स्कूल में ही एक आवश्यक विषय के रूप में रख सकें। वैदिक शिक्षा भारत की संस्कृति और समृद्ध विरासत का मूल आधार है। कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं कहा जा सकता है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और विस्तारित नहीं कर सकता है। यह अध्ययन आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के वैदिक आदर्शों के महत्व के बारे में है। इस अध्ययन की आवश्यकता आधुनिक शिक्षण संस्थानों में अनुशासन बनाए रखने और बनाने के लिए है। शिक्षक और छात्र के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध। यह अध्ययन आधुनिक पीढ़ी को यह समझा सकता है कि इंद्रियों पर पूर्ण स्वामित्व के उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए, सत्य के आदर्श, स्वतंत्रता के आदर्श, समानता के आदर्श और शांति और एकता के आदर्शों को स्थापित करने के लिए तब हमें वैदिक शिक्षा के आदर्शों को स्वीकार करने की आवश्यकता है।

वैदिक ज्ञान का अभ्यास और उपयोग वास्तव में हमें कई तरह से सहायता कर सकता है। वैदिक शिक्षा उन सभी समस्याओं का समाधान है जो हम वर्तमान में इस दुनिया में पाते हैं। हमें अब गहराई से देखने की जरूरत है। उत्तर और समाधान खोजें। नैतिक भावना के समुचित विकास द्वारा चरित्र निर्माण वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था। इसलिए सभी शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य, चाहे वह साहित्यिक हो या पेशेवर, छात्र को समाज का एक उपयोगी सदस्य बनने के योग्य बनाना होना चाहिए। शिक्षा को मनुष्य को एक निश्चित नैतिक भावना देकर और उसे अपने मूल पशु को नियंत्रित करने में सक्षम बनाकर उसके आदर्श स्वभाव का विकास करना चाहिए। प्रकृति। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य और आदर्श एक साथ और सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना था। पुरुष सामाजिक प्राणी हैं, वैदिक शिक्षा ने न केवल सामाजिक कर्तव्यों पर जोर दिया बल्कि सामाजिक सुख को भी बढ़ावा दिया।

कीवर्ड : शिक्षा, वैदिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा

भारत की ऐतिहासिक बहुभाषिकता एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान

डॉ0 मृदुल कुमार सिंह
सहायक आचार्य शिक्षा संकाय हण्डियां
पी0जी0 कॉलेज, प्रयागराज

राजेश यादव
शोधछात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर

सारांश

अनुमानतः तीन सौ पचास करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के पश्चात विकास प्रक्रिया के अनवरत गतिमान रहने से लगभग तीन करोड़ वर्ष पहले आदिमानव जो लगभग बन्दरों जैसे ही थें, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यह क्रमशः आस्ट्रालापिथेकस, होमो हैविलियस, होमोइरेक्टस, होमो सेपियन्स तथा सबसे अन्त में आधुनिक मानव अर्थात होमोसेपियन्स के रुप में उत्तरी पुरापाषाण काल में दक्षिण अफ्रीका मे प्रकट हुआ। अनुमानतः 35 हजार से 50 हजार साल के मध्य भाषा का विकास हुआ। अभिलेखी साक्ष्य के दृष्टि से 2300 ई0पू0 आद्य हिन्द इरानी भाषा जिसमे की हिन्द आर्य भाषा भी सम्मिलित के प्रमाण इराक के अगेड़ वंश के पाटिया पर लिखे गयें थे। जिनमें अरिसेन और सोमसेन नामक दो नाम मिलते है। ई0पू0 तीसरी शताब्दी में प्राकृत सम्पूर्ण वृहत्तर भारत में सम्पर्क भाषा के रुप में प्रचलित होने साक्ष्य मिलते है। प्रारम्भिक वैदिक जन हिन्द आर्य भाषा बोलते थे। जिनके भिन्न–भिन्न रुप अभी भी दक्षिण एशिया में विद्यमान है। मध्य पूर्व भारत में मुन्डा या कोल भाषा भाषी लोग तथा दक्षिण के संगमकालीन बहुत से शब्द वैदिक ग्रन्थों में पाये जाते है। यह भारतीय संस्कृति की विलक्षणता रही है कि उसमें बहुभाषायी एवं बहुसंस्कृति को आत्मसात कर लिया। कालान्तर में संस्कृति की प्रधनता देखने को मिलती है। अक्टूबर 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने पूर्व कैबिनेट सचिव श्री टी0आर0 सुब्रमणियम की अध्यक्षता में '' नवीन शिक्षा नीति के उद्भव के लिए समिति'' के गठन का निर्णय लिया। इस समिति द्वारा 7 मई 2016 को अपनी संस्तुति प्रस्तुत किया परिणाम स्वरुप 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसरो के सेवानिवृत्त निदेशक के0 कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ड्राफ्ट समिति'' का गठन किया। इस ड्राफ्ट समिति नें 31 मई 2019 को अपना प्रतिवेदन मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ0 रमेश पोखरियाल 'निशंक' को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् 29 जुलाई 2020 ने NEP-2020 को अनुमोदित कर दिया गया। एक लम्बी संवैधानिक प्रक्रिया के पश्चात 26 जनवरी 2023 को यह सम्पूर्ण देश में लागू हो गई।

मुख्य शब्द–मातृभाषा, सम्पर्क भाषा, सहायक भाषा, प्रभावी अधिगम, त्रिभाषा सूत्र, भारतीय साइन लैग्वेज (ISL)।

अध्ययन–अध्यापन की भाषा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020

डॉ0 श्याम मोहन सिंह
(असिस्टेंट प्रोफेसर–बीएड्)
राठ महाविद्यालय, पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल
उत्तराखंड।

सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से भारतवर्ष एक इकाई है, एक देश है। परन्तु, अनेकता में एकता इसकी विशिष्ट पहचान है, क्योंकि एक देश, एक राष्ट्र और एक संस्कृति होने के बाद भी, भारतवर्ष में अलग–अलग क्षेत्रों और प्रान्तों में अलग–अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारतवर्ष के संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 महत्वपूर्ण भाषाओं को स्थान दिया गया है। राज्यों का पुनर्गठन भी भाषा के आधार पर ही किया गया है। अनेक राज्यों (प्रान्तों) में स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषाओं को 'राज्य की राजभाषा' के रूप में अपनाया गया है। भाषाओं का यह वैविध्य भारत की भाषाई समृद्धता का परिचायक है, लेकिन दूसरी तरफ यह एक व्यावहारिक और वास्तविक भाषा–समस्या का उत्पादक भी है।

संविधान में 'हिन्दी' को राजभाषा का स्थान प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में अधिकांश शासकीय और न्यायालयी अभिलेख तथा पत्रावलियां अंग्रेजी में प्रकाशित होती हैं। क्षेत्रवादी राजनीति के कारण पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में हिन्दी तथा

हिन्दी भाषियों का विरोध होता है। आजीविका और पर्यटन के उद्देश्य से अन्य भाषा–भाषी क्षेत्रों में जाने या विस्थापित होने वालों को भी भाषा–समस्या से दो–चार होना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह व्यतिरेक व्यापक रूप से परिलक्षित होता है, जो एक राष्ट्र, एक शिक्षा, एक भाषा की संकल्पना को साकार नहीं होने देता।

आधुनिक भारतवर्ष की स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात गठित अनेक शिक्षा आयोगों और समितियों ने भाषा–समस्या के समाधान के सम्बन्ध में अपने–अपने सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में सर्वोपरि सुझाव त्रिभाषा सूत्र का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इस परिपेक्ष में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में "अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति और बहुभाषिकता को प्रोत्साहन तथा भाषा सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने में तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर" को भाषा शिक्षा से सम्बन्धित आधारभूत सिद्धान्त के रूप में अपनाया गया है। यह देखना रुचिकर होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अध्ययन–अध्यापन सम्बन्धी भाषा नीतियां आगे चलकर कितनी व्यावहारिक और कारगर सिद्ध होंगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा: नवगीतों के विशेष सन्दर्भ में

जयमाला दूबे (शोध छात्रा)
डी0सी0एस0के0पी0जी0 कॉलेज (मऊ)

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिम के सूल। भारतेन्दु हरिशचन्द्र जी की उक्त पंक्ति ही हमें अपनी मातृभाषा का बोध करा देती है। क्योंकि यही वह भाषा है जिसे हम सबसे पहले सीखते हैं। यही हमारी अभिव्यक्ति का सरल और सशक्त माध्यम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षण के महत्व पहचाना और नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया है भविष्य में इसके क्रियान्वयन के साथ ही यह हमारी भाषाओं और संस्कृतियों के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। मातृ शब्द के जुड़ने मात्र से ही कोई भी वस्तु हमारे मूल से जुड़ जाती है परन्तु इसी मातृभाषा का प्रयोग जब समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जैसे प्राध्यापक, रचनाकार, फिल्मकार, गीतकार करते हैं तो ये भाषाएं अजर और अमर हो जाती है। उनका संवर्धन और संरक्षण तीव्रतम होता है। नवगीत सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुयी है। इसमें रचनाकारों द्वारा गांव, समाज, नदियों आदि जो व्यक्ति के मूल/जन्म से जुड़ी हुयी है, उनको उद्घृत करते हुये रचनाएं करते हैं। अपने गांव, समाज का वर्णन अपनी मातृभाषा में ही हृदय को स्पर्श करता है। यह कार्य नवगीतकारों ने विधिवत रूप से किया है। इन्ही कारणों से प्रत्येक व्यक्ति इन रचनाओं के साथ सहज ही जुड़ जाता है। नवगीतकारों का यह प्रयास मातृभाषा के प्रति जनमानस से मातृभाषा के प्रयोग को संवर्द्धित करेगा।

अंततः यह कहा जा सकता है कि मातृभाषा को नीतियों में स्थान देकर सरकार ने मातृभाषा को गौरवान्वित किया है। यह निर्णय बच्चों के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा क्योंकि किसी भी नयी चीज को सीखना अपनी भाषा में सरल होता है और आत्मीयता से जुड़ जाता है। भविष्य में नये–नये ज्ञान को सरलता व सहजता के साथ बच्चों के सामने रोचकता के साथ प्रस्तुत करके उनको दक्ष बनाया जा सकता है, जिससे वे जीवन में सफल हो सकते हैं और हमारा देश ज्ञान के क्षेत्र में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बेहतर क्रियान्वयन मातृभाषा संरक्षण में एक बेहतर प्रयास होगा और इस प्रयास में नवगीतकारों द्वारा अपनी रचनाओं में मातृभाषा का प्रयोग मातृभाषा के संरक्षण एवं संवर्धन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करने में सफल होगी।

योग दर्शन में अष्टांग योग

डॉ0 महात्मा प्रणव कुमार चतुर्वेदी
असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास विभाग
एस0वी0एम0पी0जी0 कालेज
फाजिलनगर, कुशीनगर (उ0प्र0)

भारतीय दर्शन में योगा का अत्यधिक महत्व है। तत्व–साक्षात्कार या आत्म–साक्षात्कार के लिये योग साधना की आवश्यकता प्रायः सभी दर्शनों एवं भारतीय धार्मिक सम्प्रदायों ने मुक्तकण्ठ से स्वीकार की है। वैदिक एवं अवैदिक दर्शनों में योग की उपादेयता सर्वमान्य है। सविकल्प बुद्धि का निर्विकल्प प्रज्ञा में परिणत करने हेतु योग साधना की उपादेयता निर्विवादरुप से स्वीकृत है। संहिता आरज्यक और उपनिषद में योग की महनीयता का वर्णन उपलब्ध है। योग के कई प्रकार हैं। गीता में ज्ञानयोग, भक्ति योग और कर्म योग तथा ध्यान योग का वर्णन है। राजयोग एवं हठयोग भी प्रसिद्ध हैं। यहां हम महर्षि पतंजलि के राजयोग का ही वर्णन करेंगे क्योंकि वही योग दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है तथा सांख्य दर्शन से सम्बद्ध है। वैसे तो योग दर्शन पतंजलि मुनि से बहुत प्राचीन है, किन्तु योग–सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि ने इसे सुसम्बद्ध दार्शनिक रूप दिया है। सांख्य योग सम्बद्ध दार्शनिक सम्प्रदाय हैं। सांख्य की तत्वमीमांसा तथा ज्ञानमीमांसा को योग प्रायः उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। योग ने ईश्वर की सत्ता स्वीकार की है, अतः इसे सेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। गीता में सांख्य को ज्ञान और योग को कर्म माना गया है तथा वस्तुतः दोनों मिलकर एक हो जाते हैं।

'योग' शब्द का अर्थ है जोड़ना अथवा युक्त करना, समाहित अथवा एकाग्त होना। अपने आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करना ही 'योग' है और जिस साधन से इस प्रकार का योग एवं सायुज्य प्राप्त होता है, वह भी योग कहलाता है। अर्थात 'योग' शब्द साधन और साध्य दोनों का वाचक है।

ऋग्वेद के एक मन्त्र में यह शब्द इन्ही अर्थो में प्रयुक्त हुआ है।

यस्मादूते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन/
स धोनां योगमिन्वती।।

ऋग्वेद

योग के इस प्रधान लक्षण का प्रतिपादन यजुर्वेद में किया गया है–––

युज्जानः प्रथमं मनस्तच्वाय सविता धियः।
अग्नेयर्ज्योति र्निच्चाय्या पृथिव्या अध्याडमरत्

योग शरीर, इन्द्रियाँ और चित्त की शुद्धि के लिये आठ अंगो का वर्णन करता है जो इस प्रकार है– यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।

वैदिक कालीन शिक्षा नीति के आलोक में शिक्षा नीति 2020

डॉ0 पंचम सिंह रावत
स्वतंत्र लेखन
विकास मार्ग पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल

भारतीय जन शिक्षा का उद्गम गुरूकुलों एवं महर्षियो के आश्रमों को ही माना जाता है प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप अत्यन्त व्यापक था, यह शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिये प्रयासरत थी। यह शिक्षा वर्तमान जीवन की श्रेष्ठता हेतु कार्य न करके आने वाले जीवन की तैयारी के रूप में प्रदान की जाती थी, वैदिक शिक्षा के तीन सूत्र दृष्टि गोचर होते है। 1. ज्ञान की प्राप्ति 2. सामाजिक धार्मिक कर्त्तव्यों का समावेश तथा 3. चरित्र निर्माण वैदिक शिक्षा की नीव इतनी मजबूत थी कि यह हजारों वर्षों तक फलती–फूलती रही। वैदिक काल में महिलाओं को भी पठन–पाठन से लेकर अनेक प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कराया जाता था वे पुरूषों के साथ यज्ञों, हवनों तथा अन्य वैदिक कर्मकाण्ड़ो में बराबरी का योगदान करती थी वे छात्रों के समान गुरूकुल में ही निवास करती थी, उन्हें गृह उपयोगी शिक्षा के अतिरिक्त काव्य, सहित्य, नृत्य, गायन वादन और ललित कला की शिक्षा दी जाती थी।

गुरूकुलों में छात्रों को वर्णों के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था थी जैसे क्षत्रिय राजकुमारों को सैनिक शिक्षा प्रदान की जाती थी इसके अन्तर्गत युद्ध विज्ञान अस्त्र–शस्त्र कला तथा धनुर्विद्या आदि का ज्ञान दिया जाता था वैदिक युग में सामाजिक कर्मकाण्डों, संस्कारों को सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व ब्राहमणों को प्रदान किया गया था।

इस प्रकार वैदिक काल के महर्षि कण्व आश्रम में भी छात्रों को व्याकरण, ज्योतिष, वेद, कृषि, पशुपालन आदि शिक्षा प्रदान की जाती थी इसके अतिरिक्त अगस्त्य ऋषि आश्रय, महर्षि अत्री तथा बद्री आश्रम मे शल्य चिकित्सा संगति अस्त्र–शस्त्र का ज्ञान भी दिया जाता था।

नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा का अर्थ है। सिखने और सिखाने की क्रिया भारत की पहली शिक्षा नीति1986 बनाई गई जो मुख्यतः लॉर्ड मैकाले की अग्रेंजी प्रधान शिक्षा नीति पर आधारित थी। पुनः फिर 1992 में कुछ संशोधन किया गया लेकिन फिर भी मूलतः अग्रेंजी माध्यम पर ही केंद्रित रहा 1986 में जो शिक्षा नीति बनी थी उसमें बच्चा ज्ञान तो प्राप्त कर लेता था लेकिन रोजगार के अवसर के योग्य नही बन पा रहा था, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर डिजिटल पर बल तथा 2020 के तहत ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफार्म पर बल दिया गया शिक्षा से न केवल साक्षरता,उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबधित संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए।

''शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप का संचालन समस्यायें एवं समाधान नई शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में''।

डॉ0 प्रवेश कुमार मिश्र
विभागाध्यक्ष, बी0एड0 विभाग
राठ महाविद्यालय पैठाणी

शिक्षक शिक्षा में इन्टर्नशिप का नियोजन एक सराहनीय प्रयास है। जिस प्रकार एक कुशल माली अपनी व्यावसायिक कुशलताओं से जंगली झाड़ियों को भी आकर्षक रूप प्रदान करके उसमें आकर्षण उत्पन्न कर देता है, ठीक उसी प्रकार एक बेहतर ढंग से प्रशिक्षित शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहारों को परिष्कृत कर एक योग्य नागरिक का निर्माण करता है। इसलिये आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप के नियोजन को बेहतर ढंग से लागू किया जाय, इसके लिये सरकारी प्रयासों के अन्तर्गत इन्टर्नशिप अवधि में छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाय जो इन्टर्नशिप केन्द्र तथा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त देख रेख में किया जाय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस हेतु सरकार द्वारा स्कालरशिप का प्रावधान किया गया है। शीघ्र ही बजट में स्थान देकर इस योजना को

प्रारम्भ करने से इन्टर्नशिप की गुणवत्ता में उन्नयन होगा तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के एक निर्धारित परिधि के अन्तर्गत आने वाले विद्यालय को इन्टर्नशिप कराने की बाध्यता सुनिश्चित की जाय। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अगल–बगल के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के साथ नेटवर्क के निर्माण की योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित है। उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालयी सहयोग को बढ़ाकर इन्टर्नशिप को बेहतर बनाया जा सकता है। एक बेहतर इन्टर्नशिप का आयोजन कुशल शिक्षक निर्माण में सफल होगा।

प्राचीन शिक्षा पद्धति एवं उसकी प्रासंगिकता

1. डॉ0 रमाकान्त यादव
विभागाध्यक्ष
स्ववित्त पोषित बी0एड0
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गोपेश्वर (चमोली)
मो0 : 7830739376
E-Mail : ramakant78yadav@gmail.com

2. डॉ0 श्याम लाल
असिस्टेंट प्रो0 बी0एड0
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गोपेश्वर (चमोली)
मो0: 8126667291
E-Mail : shyambatiyata@gmail.com

प्राचीनकाल से ही भारत शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अस्मिता को अभिव्यक्ति देने और उनके उन्नयन हेतु, साथ ही समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली को विकसित करता है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों में बौद्धिक विकास के साथ–साथ शारीरिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। शिक्षा ही विद्यार्थियों में आत्म–सम्मान, आत्मगौरव तथा आत्म–संयम, विवेक, शक्ति, न्याय–शक्ति इत्यादि गुणों का उदय होता है जो उसके व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक थे। गुरूकुल (अर्थात गुरू का परिवार) प्राचीन शिक्षा पद्धति का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। गुरूकुल शिक्षा के दौरान शिष्य अपने–अपने घरों से दूर रहकर गुरू के घर पर निवास कर शिक्षा ग्रहण करता था। गुरूकुल में गुरू के समीप रहते हुए शिष्य उसके परिवार के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता था तथा गुरू भी उसके साथ पुत्रवत व्यवहार करते थे। पुरातन भारतीय शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के लिए शिक्षा की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की गयी थी, कि उसे सचरित्र होने की प्रेरणा मिलती रहे और वह तद्नुसार अपने को विकसित करता रहे। आचार्य ने न केवल शिष्य की बौद्धिक प्रगति का ध्यान रखता था, अपितु उसके नैतिक आचरण की निगरानी भी करता था। विद्यार्थियों के समक्ष महापुरूषों व महान स्त्रियों के चरित्र का आदर्श प्रस्तुत किया जाता था, जिससे शिष्य के चरित्र निर्माण में प्रेरणा मिलती रहे।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में गुरूकुल प्रणाली शिक्षा व्यवस्था की भूमिका कम होती जा रही है। शिक्षा के अनेक संसाधन होते हुए भी विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रूचि कम होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण पाठ्यक्रम का अरूचिकर होना तथा अभिभावकों की शिक्षा के प्रति निष्क्रियता भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षा को प्रासंगिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि छात्र केन्द्रित पाठ्यक्रम को बढ़ावा मिले।

महत्वपूर्ण शब्द– अभिव्यक्ति, उन्नयन, प्रासंगिकता, गुरूकुल, पुरातन, प्रणाली, पाठ्यक्रम।

शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में तकनीकी का प्रयोग एवं नवाचार

डॉ0 गोपेश कुमार सिंह
विभागाध्यक्ष (शारीरिक शिक्षा विभाग)
राठ महाविद्यालय पैठाणी,
पौड़ी–गढ़वाल, उत्तराखण्ड

शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता को विकसित करने की प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति के ज्ञान, आचरण, दक्षता, सदाचार एवं व्यक्तित्व में बदलाव संभव है। शिक्षा और शारीरिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। जहां शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित शक्ति में वृद्धि की बात करती है, वही शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सर्वागीण विकास संभव है। ए0आर0वेमैन के अनुसार "शारीरिक शिक्षा, शिक्षा का वह भाग है, जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रशिक्षण के साथ–साथ पूर्ण विकास होता है।"

प्राचीन भारत में मनुष्य के सर्वागीण विकास हेतु "गुरूकुल" हुआ करते थे, जहां विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ ही शारीरिक शिक्षा एवं खेलों का ज्ञान प्रदान किया जाता था। समय, काल, परिस्थितियों के परिवर्तन के पश्चात् शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में गिरावट आयी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के उत्थान हेतु विभिन्न समितियों एवं संस्थाओं का गठन हुआ। जहां व्यक्ति के अंतर्निहित शक्ति के विकास एवं खिलाड़ियों की गुणवत्ता को बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया गया। यह प्रयास भारतीय परिस्थितियों, तकनीक एवं अल्प सुविधाओं को देखते हुए उत्साहवर्धक था।

वर्तमान समय में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों को सरल, उपयोगी, प्रासंगिक एवं व्यवहारिक बनाने हेतु सूचना, विज्ञान एवं संचार क्रान्ति का सदुपयोग किया जा रहा है और नवाचार के माध्यम से पाठ्यक्रम को रोजगार उन्मुख एवं रूचिकर बनाया जा रहा है। नवाचार के द्वारा खिलाड़ियों के मूलभूत कौशल में सुधार करते हुए परम्परागत शिक्षा पद्धति को वर्तमान परिवेश के अनुरूप परिवर्तित किया जा रहा है। इस हेतु नई शिक्षा नीति–2020 का लागू होना मील का पत्थर साबित हो रहा है। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में तकनीक एवं नवाचार के प्रयोग से वर्तमान भारत खेल क्षेत्र में अनेकों उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। इस श्रृंखला को बनाये रखने हेतु तकनीक एवं नवाचार का लगातार प्रयोग शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के गुणोत्तर विकास में सहायक हो सकता है।

शिक्षक शिक्षा में ई–लर्निंग की उभरती प्रवृति

मनीष मोदनवाल
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग)
श्री लालबहादुर शास्त्री डिग्री कालेज
गोण्डा (उ0प्र0)

शिक्षा प्रत्येक समाज या राष्ट्र के उत्तम निर्माण का मुख्य साधन है। शिक्षा व्यवस्था से ही उस देश की आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक प्रगति का निर्धारण करती है। शिक्षा की व्यवस्था में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है, शिक्षक ही शिक्षा के स्तरों को निर्धारित करता है। अतः शिक्षकों को अपने विषय का प्रकाण्ड विद्वान तथा उस विषय के ज्ञान को स्थानातंरित करने के लिए इनमें विभिन्न प्रकार के कौशलों तथा गुणों का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए वर्तमान समय में शिक्षकों का सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है। अतः शिक्षक जन्म–जात होते है, इस आवधारणा में परिवर्तन आया है। अब शिक्षक बनाया भी जा सकता है।

एक बेहतर शिक्षक बनाने के लिए उनको बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। भारत में शिक्षक शिक्षा का संचालन एन0सी0टी0इ0 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नामक संस्था के द्वारा किया जाता है। वर्तमान युग तकनीकी का युग है। शिक्षा के ही द्वारा इसका विकास व उचित प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान में प्राचीन शिक्षण पद्धति का स्थान तकनीकी ने ले लिया है।

शिक्षा व्यवस्था में जब तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो इस माध्यम से दी गई शिक्षा को ई–लर्निंग शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत रखा जाता है। ई–लर्निंग का अर्थ है, ई–इलेक्ट्रानिक, लर्निंग–अधिगम, सीखना अर्थात् ई–लर्निंग के अन्तर्गत सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक समर्थित शिक्षा और शिक्षण के रूप में जाना जाता है। ई–लर्निंग कौशल में कम्प्यूटर का ज्ञान एवं नेटवर्क आधारित अध्ययन किया जाता है।

यदि हम अपने देश को तकनीकी से युक्त और सुदृढ़ बनाना चाहते है तो इसके लिए शिक्षकों को ई–लर्निंग का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में ई–लर्निंग को अनिवार्य रूप से आवश्यक किया जाये। वर्तमान समय में शिक्षण कार्य को प्रौद्योगिक, वैश्वीकरण जैसे तत्वों ने प्रभावित किया है अर्थात् व्यावसायिक हो गया है। इस कारण आज शिक्षकों को शिक्षा में भी तकनीकी की आवश्यकता महसूस होने लगी है।

इक्कीसवीं सदी में प्राचीन योग पद्धति का महत्व

राम सिंह नेगी
सहायक प्राध्यापक
शारीरिक शिक्षा विभाग,
राठ महाविद्यालय पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

सारांश

इक्कीसवीं सदी के इस आधुनिक विश्व में हमारा पर्यावरण अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। और हम मनुष्य अधिक से अधिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव से पीड़ित हैं। आज विश्व इस तनाव का सामना करने के नवीन तरीके खोज रहा है और इसके लिए हमारी प्राचीन योग पद्धति एक कारगर रचना है। योग का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सधभाव की उपलब्धि प्राप्त करना है। योग एक आंतरिक अभियान है जो स्वयं के बारे मे जागरूकता और समझ पैदा करता है और आपको आत्म परिवर्तन की ओर ले जाता है यह एक आत्म विकास का मौलिक विज्ञान है जो आपके मन और शरीर सुधिकरण करता है। और उनके बीच सही संतुलन और सामंजस्य बनाये रखता है दूसरे शब्दो में यह आपके मन, शरीर और सांसो को नियत्रित करने और हमारे भीतर छिपी सम्भावित ऊर्जाओं को खोलने की एक कला है। योग घ्यान के रूप में भी हो सकता है और व्यायाम का भी एक रूप हो सकता है। कई लोग अपनी निजी जिन्दगी में इतने व्यस्त हो गये हैं कि सांस लेने का सही विधि भी भूल गये हैं योग अच्छे जीवन और शरीर के लाभ के लिए जीने की एक विधि है। योग एक ऐसी तकनीक है जिससे बिना किसी प्रशिक्षक, उपकरण और औषधि के किसी भी इंसान का शरीर स्वस्थ रह सकता है। इस प्रकार इस शोध पत्र का उद्देश्य इक्कीसवीं सदी के आधुनिक समय में प्राचीन योग की भूमिका और उसके महत्व के साथ–साथ इस समकालीन समय में मनुष्य पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : उच्च शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में एक अर्न्तदृष्टि

डॉ० जितेन्द्र कुमार नेगी
वरि० सहा० प्रोफेसर
राठ महाविद्यालय पैठाणी
ईमेल- jitendranegi496@gmail.com
मो0 : 7409783331

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शि़क्षा से उच्च शिक्षा के साथ–साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये व्यापक रूप रेखा तैयार करती है। इसका उद्देश्य धर्म, लिंग,जाति या पंथ के किसी भी भेदभाव के बिना सभी को बढ़ने और विकसित होने के लिये एक समान मंच प्रदान करना और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौजूदा जीवंत ज्ञान समाज को बनाए रखना और उसकी देखभाल करना है। यह भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में

सार्थक कदम है। इस नीति में यह परिकल्पना की गयी है कि हमारे संस्थानों के समान पाठ्यक्रम और छात्रों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करनी चाहियें। इस नीति का दृष्टिकोण छात्रों के मध्य ज्ञान, कौशल, आत्म विश्वास, बुद्धि और कर्म के साथ न केवल विचार बल्कि मुल्यों और दृष्टिकोणों में भी विकास और जीवन का समर्थन करते है और वैश्विक कल्याण के लिये एक जिम्मेदार प्रतिबद्धता ,जिससे वास्तव में वैश्विक नागरिक प्रतिबिम्बित होता है।

गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए जो उत्कृष्ट, विचारशील और अच्छी रचनात्मक प्रवृत्ति के हों।

नवीन शिक्षा नीति पांच स्तम्भों पर केन्द्रित है। वहनीयता, अभिगम्यता, गुणवत्ता, न्यायपरस्ता और जवाबेही–निरन्तर सीखने की प्रक्रिया का सुनिश्चित करने के लिये। इसे समाज और अर्थव्यवस्था में ज्ञान की माँग के रूप मे नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है।

नवीन शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों मे महत्वपूर्ण सुधार है, यह अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिये तैयार करती है, जिससे वे नये डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस प्रकार नई शिक्षा नीति बहु–विषयकता, डिजिटल साक्षरता लिखित संचार, समस्या समाधान, तार्किक तर्क और व्यावसायिक प्रदर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डालती है।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन'

'An analytical study of the economic effect of NEP 2020'

डॉ० कपिल
अस्टिेंट प्रोफेसर राजनीति विभाग
रा० महा० वि० कण्वघाटी कोटद्वार
मो0 : 07579290690

डॉ० अनुराग शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य
रा०महा०वि० कण्वघाटी कोटद्वार
dranuragsharma.1@gmail.com
मो0 : 09411038633

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक एवं कौशल विकास की अवधारणा पर अत्यधिक जोर दिया गया है। इस नीति में तकनीकी विकास के द्वारा आत्मनिर्भर भारत का सपना बुना गया है। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में गुणवत्ता को उच्चतम करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज का युवा कल का भविष्य होगा उन्हें तकनीक, कौशल तथा प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार करने के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी तथा कौशलपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की गई है। भारत की अर्थव्यवस्था सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नवीन व्यवस्थाओं से देश में आर्थिक विकास के अपार अवसर विद्यमान हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

संकेत शब्द – राष्ट्रीय, शिक्षा, नीति, कौशल, आर्थिक

वर्तमान समय में प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की उपयोगिता

डॉ0 दिनेश साहू
सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग
सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सारांश

जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा के बिना मनुष्य बुद्धिमान और विनम्र नहीं बन सकता। प्राचीन भारतीय शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करता था। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसे गुण थे जिनमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक योग्य नागरिक और जिम्मेदार सदस्य बन कर सदैव अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करता आ रहा था। आज की भारतीय शिक्षा व्यवस्था मैकाले की देन है। इस शिक्षा प्रणाली और प्राचीन शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा अंतर दृष्टिगोचर होता है। 1923 ई. में लॉर्ड विलियम ने लॉर्ड मैकाले को भारत की शिक्षा पद्धति में सुधार की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कहा था कि इस शिक्षा से मेरा एक ही उद्देश्य है कि भारत में अधिक से अधिक क्लर्क पैदा हों, जिससे यह देश बहुत दिनों तक गुलाम बना रहे। हमें वर्तमान समकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत की पुरानी शिक्षा संस्कृति को अपनाना चाहिए। प्राचीन काल की अध्ययन पद्धति व्यावहारिक एवं प्रयोगात्मक होने के कारण इस विद्या का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जा सकता था। प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर उसे एक सक्षम नागरिक बनाना भी था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : उच्च शिक्षा में परिवर्तन एवं क्रियान्वयन

प्रतिभा यादव
शोधछात्रा (शिक्षाशास्त्र)
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर
विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0)

सारांश

सम्पूर्ण मानव शक्ति को प्राप्त करने के लिये तथा न्यायसंगत समाज का निर्माण करने व राष्ट्रीय उन्नति के लिये शिक्षा सब से आवश्यक संसाधन है। वर्तमान में भारत दुनिया का सब से अधिक आबादी वाला देश होने के साथ ही सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश भी बन गया है। इन युवाओं को गुणवत्तापुर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ही भारत की उन्नति सम्भव है। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस तीव्र गति से बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं कि पूर्ति हेतु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधारात्मक परिवर्तन अतिआवश्यक है। इस दिशा में केन्द्रीय सरकार का सकारात्मक पहल नई शिक्षा नीति को तैयार करना है। राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई, 2020 को स्वीकृति प्रदान की गयी। यह 21वीं सदी की पहली और स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिये अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यह नीति प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परम्परा के आलोक में तैयार की गयी है। भारत द्वारा वर्ष 2015 में अपनाये गये सतत् विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य संख्या चार में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार, विश्व में वर्ष 2030 तक'' सभी के लिये समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।'' इस बहुउद्देश्यीय लक्ष्य की पूर्ति हेतु सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा दिये जाने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में आमूल–चूल परिवर्तन किये गये हैं। इस नीति में उच्चतर शिक्षा में समानता तथा समावेसन पर बल दिया गया है ताकि सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुँच सुनिश्चित की जा सके। डिग्री कार्यक्रमों की अवधि एवं संरचनानुसार परिवर्तन किये गये है। स्नातकस्तर की शिक्षा को 4 वर्षीय किया गया है, जिस में प्रमाणन के साथ निकास के अनेक विकल्प दिये गये हैं। इसके अन्तर्गत एक वर्ष के उपरान्त प्रमाण पत्र, दो वर्ष बाद डिप्लोमा, तीन वर्ष बाद डिग्री तथा चार वर्ष के बाद

शोध सहित उपाधि प्रदान की जायेगी। विभिन्न शिक्षण संस्थानों से प्राप्त किये गये क्रेडिटों को डिजिटल रुप में एकत्रित करने हेतु एक अकादमिक क्रेडिट बैंक को बनाने का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 में विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमो को चलाने का सुझाव दिया गया हैं, जो निम्नवत हैं– (1) तीन वर्ष का स्नातक शिक्षा पूरी करने वालों के लिये दो वर्षीय पाठ्यक्रम, (2) शोध सहित चार वर्षीय स्नात्तक शिक्षा पूरी करने वालों के लिये एक वर्षीय पाठ्यक्रम (3) पाँच वर्षीय एकीकृत स्नात्तक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पी०–एच०डी० के लिये स्नातकोत्तर डिग्री या शोध सहित चार वर्षीय स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी जबकि एम०फिल कार्यक्रम को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। उच्च शिक्षा को सर्व सुलभ, लाभकारी व प्रभावशाली बनाने हेतु इसके क्रियात्मक प्रणाली में भी परिवर्तन किया गया है। उच्चतर शिक्षा में विनियमन, प्रत्यायन, निधियन एवं मानकों के निर्धारण हेतु एक विशाल निकाय ''भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग'' (HECI) के तहत कार्य किया जायेगा। इस आयोग का पहला अंग ''राष्ट्रीय शिक्षा विनियामक परिषद'' (NHERC) होगा, दूसरा अंग 'राष्ट्रीय प्रात्यायन परिषद' (NAC) होगा, तीसरा अंग 'उच्च शिक्षा अनुदान परिषद' (HEGC) होगा, तथा चौथा अंग सामान्य शिक्षा परिषद (GEC) होगा।

राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 में विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा द्वारा 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षा में 2018 के 26.3 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारितहै।

सार रूप में यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, को मंजूरी प्रदान की है, अगर उसका क्रियान्वयन सही तरीके से होता है तो आशा है कि यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आयेगी।

शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग एवं नवाचार

कु0 यशोदा
शिक्षाशात्र विभाग
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर (उ0 प्र0)

सारांश

21वीं सदी सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के विकास की सदी है। सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के संसाधनों ने आज सम्पूर्ण विश्व को एक गाँव में परिवर्तित कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र मे तकनीकी एवं नवाचार के प्रयोग से चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिल रहे है। आज शिक्षा प्रणाली में तकनीकी को अपनाना अनिवार्य हो गया है। अध्ययन–अध्यापन, नियोजन, प्रशासन, मुल्यांकन आदि में तकनीकी का प्रयोग बढता जा रहा है। आज जो छात्र अध्ययन में तकनीकी का प्रयोग नहीं करते वे अपने आप को इस प्रतियोगिता के युग मे पीछे खड़ा पाते है। वर्तमान जीवन शैली एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 34 साल बाद लायी गयी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मे आमूल–चूल परिवर्तन किये गये है। इस शिक्षा नीति में शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग एवं नवाचार पर अत्यधिक बल दिया गया है ताकि सभी तक शिक्षा की पहुँच सम्भव हो सके। सबके लिए समान पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तम्भों पर आधारित यह शिक्षा नीति सतत् विकास का एजेण्डा 2030 के अनुकूल है। इस शिक्षा नीति के तीसरे भाग के अन्तर्गत शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के गठन की बात कही गयी है। अतः इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 21वीं सदी के स्कूली और उच्चतर स्तर के शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, समग्र तथा लचीला बनाते हुए छात्र का सर्वांगीण विकास कर राष्ट्र को एक ज्ञान आधारित समाज के रुप में प्रतिष्ठित करना है।

मुख्य शब्द– शिक्षा, सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी, नवाचार, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षिक प्रोद्योगिकी मंच।

शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग एवं नवाचार

मनीष कुमार वर्मा
शोध छात्र
(शिक्षा शास्त्र विभाग)
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर (उ० प्र०)

सारांश

शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। यह विकास का मूल आधार है।किसी भी राष्ट्र का विकास शिक्षा के अभाव में असंभव है, चाहे वह राष्ट्र कितने भी प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्यों न हो । आज के बदलते परिवेश में परिवर्तन के धारा ने शिक्षा को विशेष रूप से प्रभावित किया है। विज्ञान के बढ़ते चरण ने शिक्षा की दशा व दिशा दोनों ही परिवर्तित किये हैं। मनुष्य ने तकनीकी उन्नति के माध्यम से स्वयं का जीवन उन्नत किया है ।

भारत के सन्दर्भ में देखा जाये तो पिछले तीन दशकों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे तकनीकी एवं नवाचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का अत्यधिक विस्तार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र मे इसका पर्याप्त उपयोग बढ़ा है। प्राचीन गुरुकुल तथा आश्रम की मौखिक परम्परा से होते हुए आज विद्यालय, विश्वविद्यालय एवं विभिन्न शोध संस्थान स्थापित हो चुके हैं । शिक्षा की पारम्परिक विधियां ब्लैक बोर्ड तथा चॉक के दौर से गुजरते हुए वर्तमान विद्यालयी शिक्षा नवयुगीन साधनों तथा तकनीकियो से सुसज्जित होती जा रही है। शैक्षिक तकनीकी में नवाचार के में रूप कम्प्यूटर का प्रयोग तीव्र गति से हो रहा है। इसके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से छात्र सीधे सक्रिय होते हैं। नवाचार शैक्षिक व्यवस्था और शिक्षण कार्य प्रणाली को मजबूत बनाये रखने के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तकनीकी है। इसका प्रयोग वर्तमान के साथ–साथ भविष्य की अपेक्षाओ की भी पूर्ति करने में सहायक है । नवाचार से शिक्षण में गुड़ात्मक उन्नयन होता है तथा शिक्षा को दिशा बोध प्राप्त होता है । जिसमे व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (उच्च शिक्षा में परिवर्तन एवम् क्रियान्वयन)

शैलेश कुमार यादव
(असिस्टेंट प्रोफेसर)
शिक्षक शिक्षा विभाग
किशोरी रमण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
मथुरा (उ० प्र०)

सारांश

शिक्षा किसी देश का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, इसके द्वारा देश की जनसंख्या को संसाधन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। भारत एक विकासशील देश है, अतः यहां शिक्षा विशेष रूप से आवश्यक है। वर्तमान में भारत की अधिकांश जनसंख्या युवा है जिसकी औसत आयु लगभग 26 वर्ष से कम है।अध्ययनोंके अनुसार भारत 2026 में औसत 29 वर्ष आयु के साथ सबसे युवा राष्ट्र होगा। इस जनसंख्या को लाभांश में परिवर्तित करने के लिए शिक्षा एक आवश्यक साधन है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़े फैसले लिए हैं।

- प्रथम – केंद्रीय मानव संसाधनव विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) किया है।
- द्वितीय – नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को स्वीकृति दे दी है।
- यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पूर्व वर्ष 1968में और 1986 में शिक्षा नीति लायी गई थी। 1986 में लायी गई नीति को 1992 में संशोधित किया गया था। 34 वर्ष बाद यह नई नीति लाई गई है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए 2015 से ही प्रयास प्रारंभ कर दिये गये थे। 2016 में पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यन की कमेटी ने नई शिक्षा नीति पर रिपोर्ट पेश की थी। जून 2017 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदे के लिए समिति गठित हुई, जिसने 31 मई, 2019 को रिपोर्ट सौंपी। इनके आधार पर इस नीति को तैयार किया गया है।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर को 2020–2035 तक बढ़ा कर 50% करना। 2018 में यह दर 26.3% थी। उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 3.5 करोड़ नई सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- उच्चस्तर पर व्यापक आधार वाली, बहु–विषयक, समग्र स्नातक शिक्षा का प्रावधान, जिसमें पाठ्यक्रम लचीला, रचनात्मक और व्यावसायिक शिक्षा से समन्वित होगा।
- उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए एकल विनियामक बनाया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बैचलर डिग्री चार साल की की जाएगी। हालांकि 3 साल का भी विकल्प रहेगा। जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश बीच में कोर्स छोड़ेंगे, उन्हें भी क्रेडिट ट्रांसफर और एक ब्रेक के बाद अपनी डिग्री पूरी करने का मौका मिलेगा।
- 12वीं के बाद कॉलेज स्तर पर चार विकल्प होंगे। चार साल के बैचलर कोर्स में पहला साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, दो साल पर एडवांस डिप्लोमा, तीन साल पर बैचलर डिग्री और चार साल पर रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री कोर्स पूरा कर सकते हैं। यानी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प मिलेगा।
- अगले 15 साल में कॉलेजों को डिग्री देने की स्वायत्ता प्रदान कर दी जाएगी। कॉलेजों के लिए यूनिवर्सिटीज से मान्यता की जरूरत नहीं होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी खत्म किया जाएगा।
- विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से कुछ को भारत आने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। शीर्ष भारतीय संस्थानों को वैश्विक बनाने का प्रायस किया जाएगा।
- 2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मल्टीडिसिप्लीनरी बनाया जाएगा। पाली, प्राकृत, पर्सियन के लिए यूनिवर्सिटी कैंपसों में ही राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

- मास्टर डिग्री कोर्स के बाद पीएचडी से पहले एमफिल कोर्स नहीं होगा।
- नई शिक्षा नीति के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6%शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। शिक्षा पर जीडीपी के 6%खर्च की संस्तुति 1968 की शिक्षा नीति के अनुमोदक कोठारी के द्वारा भी की गई थी। जिसे शिक्षा नीति 2020 में अंततः स्थान दिया गया है। यह बहुत ही उत्साह जनक बात है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 के अनुसार भारत में 2017 में जीडीपी का मात्र 2.7% खर्च किया गया था। यह एक विकासशील राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है।
- भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। देश में तीन दशक के इंतजार के बाद नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। इस नीति का सफल क्रियांवयन देश में उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था और उज्ज्वल भविष्य की आशा व्यक्त करता है।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण प्रकिया में नवीन तकनीकी के उपयोग का अध्ययन

अरविन्द कुमार
असि0 प्रो0 - बी0एड्0
राठ महाविद्यालय पैठाणी

सारांश

किसी भी व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देश की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की संरचना में समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। जिससे समाज की आवश्यकताओं के विभिन्न कार्यों को कुशलता से करने में सफलता प्राप्त की जा सके। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की नवीन शिक्षण विधियों का उपयोंग किया जाना चाहिए। जिससे कि विषय व प्रकरण का ज्ञान व आवश्यक कौशल छात्र–छात्राओं में विकसित किया जा सके। इस विचार को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण कार्य में नवीन शिक्षण विधियों एंव तकनीकी के उपयोग पर बल दिया गया है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों में आधुनिक समाज की आवश्यकता के अनुसार नवीन तकनीकी के द्वारा छात्र–छात्राओं को पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा में नवीन तकनीकी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। सरकार व शिक्षा प्रशासकों का योगदान इस क्षेत्र में क्या योगदान होना चाहिए। शिक्षकों व शिक्षक प्रशिक्षकों को इस प्रक्रिया हेतु कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। साथ ही नवीन विकसित ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कैसे किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में चुनौतियां एंव समाधान क्या–क्या हैं। शिक्षा में नवीन तकनीकी ज्ञान व साधनों का उपयोग समाज व व्यक्ति के विकास में कैसे सहायक हो सकता है। विविधताओं से सृजित वृहद भारत देश की जनसंख्या को विभिन्न विषयों एंव कार्यों में कुशलतायुक्त व साधन सम्पन्न कैसे विकसित किया जा सकता है।

मुख्य शब्द – शिक्षा, आधुनिक शिक्षण विधियां, शिक्षा तकनीकी, शिक्षा में तकनीकी के उपयोग के विभिन्न आधुनिक माध्यम व साधन, शिक्षा में तकनीकी के उपयोग के लाभ।

शिक्षा में नवाचार

डॉ0 बीरेन्द्र चन्द,
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, रक्षा अध्ययन विभाग,
राठ महाविद्यालय पैठाणी,
पौड़ी-गढ़वाल, उत्तराखण्ड

सारांश

उच्च शिक्षा तन्त्र को और ऊँचाई में पहुँचाने के लिए दुनिया के विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, और हम दुनिया के विश्वविद्यालय के साथ अपनी तुलना करे तो हम बौने साबित हो रहे है इसलिए जो भी उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उसको जहाँ भी सेमीनार, वेबिनार या अन्य माध्यमों से जानकारी मिलती है वो उसे अपने संस्थान को

अवगत कराना चाहिए क्योंकि एक जानकार शिक्षक कितनों को जानकारी दे रहा है, उससे बहुत छात्र/छात्राओं में जागरूकता आ रही है।

हमारे संस्थान का वातावरण कितना अच्छा हो रहा है, हर एक कर्मचारियों का कर्तव्य है कि वह अपने संस्थान को आगे करने के लिए दिलोजान से कार्य करने से ही हम इस मूकाम में पहुँच सकते है "क्योंकि हम विद्यार्थियों को सीखा सकते है"। This is the new experience, New Era में एक वैज्ञानिक ने कहा था– "One a new technology over you if you are not part of the steamroller you are part the road"

नई चीज सिखने को मिल रही है, और साथ–साथ विद्यार्थियों को भी सीखा रहे हैं, e-class, e-library, Whatsapp Group, There are more than 3 crore digital resources available here a open education Resources a full University collection Resource, इसलिए हम अपने आपको अपडेट रखेगे, हमारा संस्थान अपने आप अपडेट होगा और विद्यार्थियों की भी जिज्ञासा बढ़ेगी।

खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास में नई शिक्षा नीति-2020 की भूमिका

डॉ0 गिरजा सिंह
अतिथि प्रवक्ता
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, (उ0प्र0)

सारांश

खेल, मानव की जन्मजात क्रिया है। बालक जन्म के पश्चात् ही हाथ, पैर हिलाने की गतिविधियों को करता हुआ दिखाई देता है। समय के साथ बालक चलने, दौड़ने, कूदने एवं फेकने की क्रिया करता है। बालक द्वारा किये गये इन्ही क्रियाओं के व्यवस्थित रूप को खेल कहा गया है। खेल, कई नियमों एवं रिवाजों द्वारा संचालित की जाने वाली एक प्रतियोगी गतिविधि है। खेलों के द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप वह एक खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है और अपने देश का नाम विश्व पटल पर गौरवान्वित करता है।

प्राचीन भारत में शिक्षा का केन्द्र "गुरूकुल" हुआ करते थे, जहां बालक को व्याकरण, अस्त्र–शस्त्र, व्यायाम एवं योग की शिक्षा के साथ कुश्ती, नृत्य, दण्ड–बैठक, तलवारबाजी आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों, वेदों व पुराणों से प्राप्त होता है।

किसी राष्ट्र की उन्नति वहां की शिक्षा व्यवस्था एवं स्वस्थ नागरिकों पर निर्भर करती है। प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य पर कार्य करता है। यह उद्देश्य शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों को प्रमुखता से सम्मिलित करने से प्राप्त किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा को क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। यह केवल शारीरिक क्रियाकलापों तक सीमित नहीं है। अपितु इसमें व्यक्ति के विकास के सभी पहलू जैसे मानव जीवन के सभी क्रिया–कलाप, स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रकृति, पर्यावरण आदि शामिल है।

समय, काल, परिस्थितियों के परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और खेलों को शिक्षा नीतियों में पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन के विकास के लिए अनेकों कोर्स, नीतियां, योजनाएं एवं संस्थायें बनायी गयी। जिसके सहयोग से खिलाड़ियों का विकास संभव हुआ और उन्हें कुछ हद तक रोजगार उन्मुख बनाया जा सका। भारत सरकार के इन्ही प्रयासों के अंतर्गत "नई शिक्षा नीति–2020" शारीरिक शिक्षा, खेल एवं खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख कदम है। मेरा मानना है कि "नई शिक्षा नीति–2020" के पूर्णतः लागू होने से खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के साथ ही अपना देश भारत विश्व पटल पर पुनः विश्वगुरू बनकर उभरेगा।

कला और संस्कृति का संवर्धन एवं संरक्षण

डॉ0 लक्ष्मी नौटियाल
(असि0 प्रो0) हिन्दी विभाग कला-संकाय,
राठ महाविद्यालय पैठाणी

सारांश

भारत एक ऐसा देश है जिसमें संस्कृति एवं कला का अथाह समुद्र भरा पड़ा है, और इसी संस्कृति से प्रेरित होकर विदेशी भी इस संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं। 'अतिथि देवो भवः' यहाँ की संस्कृति के रग–रग में बसा हुआ है। यहाँ की संस्कृति नैतिक मूल्यों की पहचान है और आने वाले समय में इसी संस्कृति के नैतिक मूल्य एक न एक दिन भारत को अवश्य ही विश्व गुरु के नक्शे की पहचान बनायेगे संस्कृति किसी क्षेत्र विशेष अथवा भूभाग में निवास करने वाले जन समुदाय की अमूल्य धरोहर हैं। किसी क्षेत्र विशेष में उसकी संस्कृति की जड़े बहुत गहरी होती हैं।

संस्कृति मनुष्य जीवन का वह आचार–व्यवहार होती है जिससे उसके सम्पूर्ण जीवन की दिशा तय होती है। भारतीय संस्कृति के विविध आयाम होते हुए भी यहाँ अनेकता में एकता के दर्शन दिखाई देते हैं।

भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों की लोक संस्कृति एवं लोक कलाएं समग्र भारत की संस्कृति एवं कलाएं मानी जाती है। और यहाँ संस्कृति का रूप देश और राष्ट्र के संदर्भों में बहुत व्यापक हो जाता है।

एक आलोचक का कहना है कि 'किसी भी प्रदेश की संस्कृति का जीता जागता चित्र उसके लोक साहित्य में प्रतिबिम्बित होता है।'

किसी भी देश की विशेष संस्कृति, जीवन तथा दर्शन और इतिहास यदि उसके साहित्य से पहचाना जाता है तो उस देश की स्थापत्य कला से भी वहाँ की संस्कृति, वहाँ के जीवन दर्शन और वहाँ के इतिहास का बोध होता है। भारत वर्ष की वास्तुकला देव मूर्तियो, मंदिरों, मठो, किलो, प्राचीरों आदि के रूप में सुरक्षित दिखाई देती है। भारत की इस सांस्कृतिक संपदा एवं वास्तुकला का संरक्षण तथा संवर्धन हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यही संस्कृति तथा कला कौशल हमारी पहचान के साथ साथ आर्थिक तथा नैतिक मूल्यों की भी पहचान कराती है तथा कला और संस्कृति का संवर्धन तथा संरक्षण कर हमें आने वाली पीढ़ी को भी इसकी पहचान करवानी होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत उसके पाठ्यक्रम में नैतिकता तथा सार्वजनिक उद्देश्य के महत्व का समावेश करना होगा। शिक्षा जगत से जुड़े समस्त विषयों की भाँति यहाँ की संस्कृति तथा कला को भी संरक्षित कर पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा ताकि आने वाले समय में युवाओं के लिये यही संस्कृति एवं कला रोजगार का साधन बन सके। इस संस्कृति एवं कला का संरक्षण हमें राज्य स्तर पर करना होगा और जब प्रत्येक राज्य अपनी –अपनी संस्कृति एवं कलाओ को संरक्षित करने का प्रयास करेगा तो स्वयं ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत की संस्कृति एवं कला का अपने आप ही संवर्धन एवं संरक्षण हो जायेगा।

डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है 'लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है उसमें भूत, भविष्य तथा वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है, लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है।'

कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा

प्रदीप कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (बी०एड०)
राठ महाविद्यालय पैठाणी

सारांश

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा अनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके शान एवं कला–कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। वर्तमान दौर आर्थिक पक्ष पर सर्वाधिक जोर दे रहा है। और इसी के आधार पर शिक्षा को सर्वोपरि उद्देश्यों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया हैं। वह शिक्षा को किसी समाज के विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न उद्देश्यों को सामने रखकर दी जाती है उसे विशिष्ट शिक्षा कहते है। इसके द्वारा मनुष्य को एक निश्चित कार्य जैसे–बढईगिरी, लोहारगिरी, कताई–बुनाई, रंगाई, वैद्य, डॉक्टरी, वकालात, इन्जीनियरिंग तथा अध्यापन आदि के लिए तैयार किया जाता है। समाज अथवा राष्ट्र के लिए कुशल कामगर, संगठनकर्ता, प्रशिक्षण और सैनिक आदि तैयार किये जाते है अतः इसे व्यावसायिक शिक्षा कहते है। इस प्रकार की शिक्षा से मनुष्य की सृजनात्मक शक्तियों को विकसित किया जाता है। उन्हें किसी उत्पादन अथवा उद्योग कार्य में निपुन किया जाता है और इस प्रकार उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने मे समर्थ किया जाता है। इससे ही कोई व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र व्यावसायिक उन्नति करता है। और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होता है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग–"शिक्षा का उद्देश्य तकनीकी प्रशिक्षण के लिए विस्तृत सुविधायें प्रदान कराना होना चाहिए"

महात्मा गांधी जी ने आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा को प्रमुख स्थान प्रदान किया। उनका विचार था कि बालक अध्ययन करते–करते कुछ काम करना तथा कमाना सीख ले तो जीवन में सदैव सुखी रहेगा। बच्चों में ज्ञान ढूढंने की अपेक्षा जीविकोयार्जन तथा स्वावलम्बी भावना का विकास आवश्यक है।

NEP 2020 में पेशेवारों को तैयार करने से जुड़ी शिक्षा के लिए इस बात पर बल दिया गया है कि पाठ्यक्रम में नैतिकता और सार्वजनिक उद्देश्य के महत्व का समावेश हो साथ ही विषय विशेष की शिक्षा और व्यावहारिक अभ्यास की शिक्षा को शामिल करने की अनुशंसा की गई है।

कृषि विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ ही अन्य विषयों के स्टैट अलोन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य अपने आप को एक बहु विषयक संस्थान के रूप में विकसित करना होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्वास्थ्य शिक्षा को पुनर्कल्पित किये जाने की आवश्यकता, तकनीकी शिक्षा में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों को शामिल करने पर विशेष बल दिया गया है। अतः शिक्षा नीति में कौशल विकास एव व्यावसायिक शिक्षा के पक्ष पर विशेष ध्यान दिया गया है।

की बर्ड :– आर्थिक पक्ष, कौशल विकास, विशिष्ट शिक्षा सृजनात्मक शक्तियां, पुनर्कल्पित

कथा साहित्य में मातृ-भाषा संरक्षण एवं संवर्द्धन

प्रियम्बदा मिश्रा
सहा0अ0-हिन्दी,
लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कॉलेज (हापुड़)

सारांश

मातृ शब्द की गूँज मात्र से मन उल्लसित हो जाता है और मन–मस्तिष्क हमारी जडों से जुड़ जाता है। मातृ–भाषा का प्रयोग हमारे मन में एक आत्मीय एहसास उत्पन्न करता है। मातृ शब्द से ही किसी के मन मे जो भाव प्रस्फुटित हो जाता है वो माता के समान ही निजी पन लिए और उसके प्रति आत्मिक प्रेम के साथ–साथ एक सम्मान का भी भाव जोड़ देता है। जो स्नेह एक पुत्र अपनी माता से करता है वो स्नेह ना तो किसी और की माता से कर सकता है और ना ही वो सम्मान दे सकता है। बिलकुल इसी भाँति मातृ–भाषा का भी स्नेह हर मनुष्य को भी होता है। भारतेंदु जी के शब्दों में–

पढ़उ लिखउ कोउ लाख विधि, भाषा बहुत प्रकार ।
पै जबहीं कछु सोचिहउँ, निज भाषा अनुसार ।।

उपर्युक्त पंक्ति में भारतेंदु जी ने मातृ–भाषा के महत्व को समझाते हुए यह बताने की कोशिश की है कि, हम कितना भी पढ–लिख ले या कितनी ही भाषा सीख ले परन्तु मन में जो कुछ भी निजी विचार उत्पन्न होते हैं वे अपनी मातृ–भाषा में ही सम्भव है।

मातृभाषा आज निरंतर विलोप की स्थिति में है। मातृभाषा के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। उसके प्रति आत्म सम्मान का भाव निहित होना चाहिए तभी मातृभाषाओं को संरक्षित किया जा सकता है। जन मानस की उपेक्षा के कारण भारत वर्ष ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त किया है जिसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। यह युनेस्को की रिपोर्ट से सिद्व होता है। भारतीय साहित्यकारों में अपनी मातृ–भाषा के प्रति प्रेम उनकी रचनाओं में प्रकट होता है। वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृ–भाषा को शिक्षण का माध्यम बना कर इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है, परन्तु आवश्यक्ता है कि हम वैश्विक भाषाओं के साथ अपनी मातृ–भाषा को सवंर्द्धित करते रहें और आने वाली पीढ़ी को सतत् हस्तानांतरित करते रहें। सरकार का यह प्रयास जन–मानस के सहयोग से ही संभव हो सकता है। इसलिए हमें संकल्प लेना होगा कि हम मातृ–भाषा के संरक्षण एवं संवर्द्धन में अपना अतुल्य योगदान प्रदान करेंगे।

नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में परिवर्तन

डा0 राकेश सिंह नेगी
सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग
हे0न0ब0 गढवाल विश्वविद्यालयश्रीनगर

सारांश

यह भारतमें 21 वींसदी की पहली शिक्षा नीति है। स्वतंत्रता के बाद यह भारत की केवल तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति 1968 में दूसरी 1986 में लागू की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है। आज भारत में लगभग 1000 से भी अधिक उच्च शिक्षण संस्थान हैं समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है। यह नीति शोध एंव विकास को महत्व देगी। सामाजिक सरोकारों से जोडने का भी काम करेगी। और उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाएगी अब तक भारतीय उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय विविधता का आभाव रहा है। इसका उददेश्य एक नई प्रणाली का निमार्ण करना है जो भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों पर निमार्ण करते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। और समग्र ,लचीला, बहुविषयक है। यह शिक्षा नीति कई मायनों में आदर्श प्रतीत होती है, लेकिन निश्चय ही इसकी सफलता इसके कुशल कार्यान्वयन पर निर्भर होगी।

राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका

रमेश कुमार प्रजापति
शिक्षाशास्त्र विभाग
म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सारांश

भारत का भाग्य अब कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। विज्ञान और तकनीकी के इस युग में यह शिक्षा ही है जो लोगों की संवृद्धि, भलाई एवं संरक्षण का स्तर निर्धारित करती है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महान कार्य में हमारी सफलता स्कूलों एवं कालेजों से निकलने वाले लोगों की संख्या तथा गुणवत्ता पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मुख्य प्रायोजन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है। यदि राष्ट्र के विकास की गति तेज करना है तो सु–परिभाषित सशक्त एवं विचारपूर्ण शिक्षा नीति का निर्माण करना होगा और शिक्षा को सशक्त बनाने, सुधारने तथा फैलाने के लिए सुनिश्चित एवं शक्तिशाली कार्य करने होगे। शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक सशक्त साधन के रूप में प्रयोग करना होगा। अतः उन दूरवर्ती राष्ट्रीय आकांक्षाओं एवं राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों के साथ जोड़ना होगा जिनमें देश लगा हुआ है और उन निकटवर्ती कठिन समस्याओं के साथ जोड़ना होगा जिनमें देश लगा हुआ है और उन निकटवर्ती कठिन समस्याओं के साथ भी जोड़ना होगा जिनका देश को सामना करना है। इस उद्देश्य के लिए शिक्षा को उत्पादन वृद्धि सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति तथा आधुनिकता की प्रक्रिया को तेज करने और सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की ओर अग्रसर करना होगा। शिक्षा राष्ट्रीय विकास का बुनियादी आधार है। शिक्षा पर लगाई गई पूंजी समूचे राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती है। इस प्रकार वह राष्ट्रीय विकास की रीढ़ बन जाती है।

राष्ट्र के किसी एक क्षेत्र के विकास को राष्ट्रीय विकास नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्र के सभी तत्व महत्वपूर्ण होते है और उनका परस्पर सम्बन्ध होता है। यदि एक भी तत्व अविकसित रहेगा तो उसका दूसरे तत्वों पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आर्थिक विकास राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण अंग है परन्तु उसे राष्ट्रीय विकास का पर्याय नहीं समझना चाहिए। राष्ट्रीय विकास राष्ट्र के विभिन्न आयामों एवं व्यक्तियों के विकास एवं पुनर्रचना की प्रक्रिया है। इसमें उद्योगों कृषि सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं की अभिवृद्धि एवं उनका विस्तार सम्मिलित है। राष्ट्र विकास का अर्थ है भारत का समूचा विकास। यह देश के किसी एक क्षेत्र के विकास तक सीमित नहीं है। संक्षेप में राष्ट्रीय विकास के अन्तर्गत अग्रलिखित है–

- ☆ राष्ट्रीय विकास लोगों को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है।
- ☆ राष्ट्रीय विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब राष्ट्रीय कार्य प्रगति की ओर लगाये जाते है।
- ☆ राष्ट्रीय विकास उन शक्तियों अथवा कारकों का एकीकरण है जिन पर देश की उन्नति का दायित्व है।
- ☆ विज्ञान एवं तकनीकी की चुनौतियों का सामना करने का विधिवत प्रयास राष्ट्रीय विकास है।
- ☆ राष्ट्रीय विकास उद्योग और कृषि तथा धनियों एवं निर्धनों में समझौता है।
- ☆ राष्ट्रीय विकास से तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्र में न्याय है।

राष्ट्र के पर्याप्त विकास के लिए सभी देशवासियों की सम्पूर्ण संलग्नता प्रतिबद्धता एवं समर्पिता अत्यन्त आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास के लिए सहायक पर्यावरण के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना पूरा योगदान देना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा का क्रियान्वयन एवं चुनौतियां ।

सुनील कुमार भट्ट
शोध छात्र, शिक्षा संकाय,
कुमाँऊ विश्वविद्यालय अल्मोड़ा परिसर

सारांश

बालक के सर्वांगीण विकास में मातृभाषा के महत्व को देखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थापित करने की पुरजोर वकालत करती है। प्रस्तुत अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा का क्रियान्वयन एवं चुनौतियां का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा हिंदी की धरातलीय स्थिति एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मातृ भाषा के क्रियान्वयन में संभावित समस्याओं का अध्ययन करना था। परिणाम दर्शाते हैं कि समाज में मातृ भाषा आधारित विद्यालयों के प्रति समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। शिक्षा माध्यम के रूप में हिंदी माध्यम विद्यालयों की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है जबकि पूर्व में गठित तमाम आयोगों की संस्तुतियों एवं नीतियों में मातृ भाषा को ही शिक्षा माध्यम के रूप में अपनाने की बात की गई है। दोषपूर्ण नीतिगत क्रियान्वयन के कारण मातृ भाषा आधारित शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः स्थापित नहीं हो पाई है। कोई भी नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसका क्रियान्वयन पूर्ण निष्ठा के साथ न किया जाए। अतः मातृभाषा को प्रोत्साहित करने हेतु सुचारु नीतिगत क्रियान्वयन की गहरी आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा आधारित शिक्षा के विचार को पूर्ण निष्ठा के साथ क्रियान्वित किया जाए। शिक्षक, शिक्षाविद, योजना निर्माता, नेता तथा समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति दोहरे चरित्र को त्याग कर स्वयं भी अपने पाल्यों की शिक्षा हेतु मातृभाषा माध्यम विद्यालयों का चयन करें।

मुख्य पद – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मातृभाषा , शिक्षा माध्यम, मातृभाषा का क्रियान्वयन, चुनौतियां।

प्राचीन भारतीय योग पद्धति

मनोज कुमार सकलानी
शोध छात्र-शिक्षाशास्त्र विभाग
महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

सारांश

योग भारतीय संस्कृति एवं परम्परा की एक अमूल्य निधि है। आत्मिक विकाय के लिए योग की महत्ता को भारतीय संस्कृति से सम्बंधित विविध धर्मग्रन्थों में निर्विवाद रूप से स्वीकारा गया है।तथा इसका विकास आदिकाल से आधुनिक काल तक लगातार होता रहा है।इतने लम्बे विकास विकास के परिणाम स्वरूप भी इसके मूल स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आया यद्यपि वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता चिकित्कसा के क्षेत्र में बढ रही है, जबकि यह मूल रूप से आध्यात्म का विषय रहा है। योग विश्व का प्राचीनतम दर्शन है इसका महत्व ऋग्वेद काल से लेकर वर्तमान काल तक निरन्तर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है।

योग का आधारभूत ज्ञान प्राचीप उपनिषद (600 वर्ष ई0 पूर्व) श्रीमद्भगवत गीता (500 वर्ष ई0 पूर्व) तथा पतंजलि योगदर्शन (300वर्ष ई0 पूर्व) आदि ग्रन्थों में उपलब्ध है। इसके बाद योगदर्शन, जैन, बौद्ध, सूफी, सिख धर्म के दार्शनिक विचारों का अंग है। 200 वर्ष ई0पू0 से लेकर 1800 वर्ष ईसा तक के वर्षों में योग विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं की साधना पद्धति का माध्यम रहा है। योग सनातन संस्कृति की एक विशिष्ट एवं पुरातन सम्पत्ति है यह मानव के व्यक्तित्व से संबंधित एक विज्ञान है। यह मन और शरीर के भीतर उर्पयुक्त ऊर्जा स्रोतों के जागरण का प्रमुख प्रेरक है। योग की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : स्कूली शिक्षा में परिवर्तन एवं क्रियान्वयन

राय साहब यादव
असिस्टेंट प्रोफेसर (बी.एड.)
गंजडुंडवारा पी.जी.कालेज गंजडुंडवारा, कासगंज

सारांश

एनईपी 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता विभाग (DOSEL) ने कार्य सूचियों के साथ कार्यान्वयन योजना का एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें प्रत्येक सुझावों के अनुसार किए जाने वाले कार्यों, जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा इनके निष्पादन , इन्हें लागू करने की समय सीमा और इनके अपेक्षित परिणामों को शामिल किया गया है। कार्य सूची के इस मसौदे को 10 सितंबर, 2020 को राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों/स्वायत्त निकायों के साथ साझा किया गया था, ताकि 12 अक्टूबर 2020 तक वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके। इस विभाग के स्वायत्त निकायों और 31 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने कार्य सूची पर 7177 सुझाव/प्रतिक्रिया दी। इनका विश्लेषण विशेषज्ञ समूहों द्वारा किया गया और कार्यान्वयन योजना क ेअंतिम संस्करण में महत्वपूण ेसुझावों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला 10 नवंबर, 27 नवंबर और 2 दिसंबर, 2020 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सचिव (SE&L) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही इसे जारी कर दिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।

पाँच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज (Foundational Stage) – 3 साल का प्री–प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2

तीन वर्ष का प्रीपेट्रेरी स्टेज (Prepatratory Stage)

तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण – ग्रेड 6, 7, 8 और

4 वर्ष का उच (या माध्यमिक) चरण – ग्रेड 9, 10, 11, 12

NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा–3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।

भाषायी विविधता का संरक्षण

NEP 2020 में कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

शारीरिक शिक्षा

विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल–कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार

इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।

कक्षा–6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी।

''राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद'' (National Council of Educational Research and Training& NCERT) द्वारा ''स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा'' (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी।

छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा–10 और कक्षा–12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक–निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।

संगीत का कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में योगदान

श्रीमती दीपा नन्दा
असिस्टेंट प्रोफेसर (संगीत)
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत (अल्मोड़ा)

सारांश

भारतीय संस्कृति विश्व की प्रचीनतम संस्कृतियों में से एक है। सृष्टि की रचना के साथ ही भारतीय संस्कृति में कलाओं का अपना विशेष योगदान रहा है। 5 प्रकार की ललित कलाओं में संगीत कला का अपना मुख्या स्थान है। भारत की समृद्ध परम्परा में यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परम्पराओं, भाषाई अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के स्थलों का महत्वपूर्ण योगदान है। संगीत विषय द्वारा भी विभिन्न संस्कारो,परम्परों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है भरिया संगीत न सिर्फ राष्ट्र अपितु व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक है। शिक्षा व्यवस्था में भी संगीत के समावेश से बालकों का मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही अपनी पहचान और अपनेपन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों और पहचानो की सराहना का भाव भी जागृत होता है। किसी भी विद्या के अस्तित्व हेतु उसका हस्तांतरण अति आवश्यक है। किसी भी विषय को सीखने या उसकी विधिवत शिक्षा हेतु प्रक्रिया का नाम ही सीखना है। सीखने या ज्ञानार्जन की यह प्रक्रिया हस्तांतरण द्वारा ही संभव है। भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, साथ ही एक शिक्षक का स्थान दिव्य रूप में भी देखा जाता है। कहा भी गया है कि

''गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा
गुरुर साक्षात परम ब्रम्ह तस्मै श्री गुरुवे नमः।''

प्राचीन काल से ही संगीत को गुरु मुख से सीखी जाने वाली कला के रूप में देखा गया है। किसी अन्य विषय को हम थोड़ा बहुत पढ़ कर भी समझ ही लेते हैं, किंतु संगीत एक प्रायोगिक विषय होने के कारण गुरु मुख से ही सीखा जाना प्रासंगिक माना जाता है। संगीत शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है।समय के बदलते चक्र में संगीत के स्वरूप में भी परिवर्तित हुए हैं। प्राचीन समय में जिस प्रकार संगीत शालाओं का वर्णन मिलता है उसी प्रकार वैदिक काल में धार्मिक क्रियाकलापों में प्रयोग किए जाने वाला संगीत पूर्णतया नियमबद्ध माना जाता था। संगीत शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व को देखते हुए इसका संरक्षण भी आवश्यक हो जाता है। नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय विद्यादान के प्रमुख स्थान माने गए हैं। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय का स्वर्णिम इतिहास स्वयं में सर्वोपरि है।

शिक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए विश्व विख्यात महान दार्शनिक प्लेटो ने संगीत का महत्व बताते हुए लिखा है– एक सफल शिक्षक संगीतज्ञ भी होना आवश्यक है, क्योंकि अन्य सभी विषयों से बढ़कर संगीत एक ऐसा माध्यम है जो न केवल मानसिकता को प्रशिक्षित करता है वरन मनोभावों को भी प्रशिक्षित करके उन्हें विशुद्ध रूप प्रदान करता है जिससे व्यक्तिगत दुर्गुण दूर हो जाता है।

नई शिक्षा नीति-2020 में खेल और खिलाड़ी का भविष्य : एक विमर्श

श्री अमित कुमार श्रीवास्तव
सहायक प्राध्यापक
मेजर ध्यानचन्द्र शारीरिक शिक्षा संस्थान
बुन्देलखण्ड वि वविद्यालय, झांसी (उ0प्र0)

डॉ0 गिरजा सिंह
अतिथि प्रवक्ता
मेजर ध्यानचन्द्र शरीरिक शिक्षा संस्थान
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (उ0प्र0)

सारांश

शिक्षा, राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। किसी राष्ट्र की समृद्धि वहां की शिक्षा नीति पर निर्भर करती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा नीति गुरूकुल आधारित थी, जहां शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के मिश्रण स्वरूप के द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता था। कालांतर में विदेशी आक्रांन्ताओं के भारत में शासन के परिणाम स्वरूप शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आया और भारतीय संस्कृति एवं उसके मूल तत्व नष्ट हो गये।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय शिक्षा नीति में क्रमशः 1968ई0 एवं 1986ई0 में सुधार किया गया लेकिन पाठ्यक्रम में खेलों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। तीसरी शिक्षा नीति–2020 में खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया है। इसके अंतर्गत युवाओं की क्षमता, गुणवत्ता एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 के ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम ढांचा उम्र के अनुसार रखा गया है। फॉउन्डेशन स्टेज से ही बालक को खेलकूद जैसी गतिविधियों के प्रयोग से पढ़ाई करायी जायेगी, उसके व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान दिया जायेगा, पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी एवं पारंम्परिक खेल को बढ़ावा दिया जायेगा।

नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय परम्पराओं, संस्कृतियों और भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलते समाज की जरूरतों के आधार पर बनाया गया है। अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में रखा गया है। शिक्षा नीति में यह बदलाव देश में खेल संस्कृति के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। मेरा मानना है कि भारतीय शिक्षा नीति में इस प्रकार के परिवर्तन को पूर्णतः लागू किये जाने से देश में खेल और खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय भाषाएँ

श्रीमती बन्दना सिंह
असि0प्रो0- बी0एड्0
राठ महाविद्यालय, पैठाणी

सारांश

भारत की भाषाएँ विश्व में सबसे ज्यादा समृद्ध, वैज्ञानिक, सुन्दर एवं सबसे ज्यादा अभिव्यंजनात्मक है। बच्चों की हृदय की भाषा उनकी मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा होती है। कई शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि बच्चे अपनी मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में जल्दी सीखते हैं तथा प्रत्यय को सरलता से समझ पाते हैं। अतः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय भाषाओ में शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है। साथ ही भारतीय भाषाओ को विस्तृत संकल्पना के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस शिक्षा नीति में विशेष रूप से बहुभाषा और मातृभाषा की शक्ति को महत्त्व दिया गया है। साथ ही साथ इस नीति में इस बात पर भी विशेष जोर दिया गया है कि विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतम गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषा/मातृभाषा में उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे विद्यार्थी दुगुने उत्साह के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओ की उपेक्षाओं के कारण शिक्षा से वंचित वर्ग भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण का लाभ विशेष रूप से उन बच्चों को मिलेगा जो मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा न जान पाने कारण विद्यालय में चुप रहते हैं और अपने भाव को व्यक्त नही कर पाने के कारण शिक्षा के प्रति उदासीन रहते हैं। वे अपनी मातृभाषा में शिक्षण का अवसर मिलने पर अपने भावाभिव्यक्ति में खुलकर हिस्सा ले सकेंगे और उत्साहित होकर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। अपनी मातृभाषा में अगर बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनका भविष्य स्वर्णिम होगा साथ ही साथ देश का भविष्य भी स्वर्णिम होगा।

प्राचीन कालीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति का महत्व

डॉ0 सीमा गौतम
एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास विभाग)
साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय,
बरेली (उ0प्र0)।

सारांश

यदि हम प्राचीन समय की गुरुकुल शिक्षा पद्धति की बात करें तो वह प्रणाली वर्तमान समय से कई गुना बेहतर थी। उससे शिक्षित होकर विद्यार्थी कुछ ना कुछ समाज के हित में समाज के लिए कार्य करते रहते थे। वर्तमान समय की भांति प्राचीन काल में विद्यार्थियों के पास सुविधाएं ना होते हुए भी वे उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया करते थे। जबकि वर्तमान शिक्षा पद्धति में उनका घर के दायित्व के प्रति समाज के प्रति कोई योगदान नहीं दिखाई पड़ता। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गुरु छात्र के साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हुए बिना लोभ लालच के अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान का निचोड अपने छात्रों के ऊपर न्योछावर कर देते थे । अभिभावक भी गुरु पर पूर्ण विश्वास करके अध्यापन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया करते थे ।छात्रों को औपचारिक शिक्षा के साथ–साथ मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक रूप से सक्षम बनाया जाता था। युद्ध कला, घुड़सवारी, तीरंदाजी आदि के साथ–साथ संस्कारों की स्थापना परम आवश्यक थी। गुरु को पूरा अधिकार होता था कि वह कौन सी पद्धति से अपने छात्र को कैसे विकसित करेगा, उसको कब प्रोत्साहित करेगा, उसको कब दंड देगा, कब उसकी अकस्मात परीक्षा लेकर उसके ज्ञान का आकलन करेगा । गुरुकुल शिक्षा पद्धति में छात्र सर्वांगीण रूप से विकसित होकर अपने घर लौटता था तो एक सुयोग नागरिक साबित होता था। आज के भौतिकता वाद और आधुनिकता के दौर में विद्यार्थी अपने मानवीय मूल्यों और संस्कारों की अपेक्षा करता हुआ नजर आता है ऐसे में पुनः एक बार हमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति के महत्व को समझना पड़ेगा ।

मुख्य शब्द– गुरूकुल, पद्धति, आध्यात्मिक, सर्वांगीण।

प्राचीन भारत में योग शिक्षा पद्धति

ले0 डॉ0 पंकज सिंह
वरिष्ठ सहायक आचार्य
डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ (उ0प्र0)।

सारांश

भगवद्गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ''योगः कर्मसु कौशलम्'' अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है। यह एक स्थापित तथ्य है कि 'योग' भारतीय मनीषा अथवा भारत–भारतीय के अथाह सनातन ज्ञान कोष की हजारों वर्ष पुरानी अमित ज्ञान शिला है जो वर्तमान में भी न केवल प्रांसगिक अपितु लोकप्रिय जीवन शैली बन चुकी है। योग दर्शन के चार पद है समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ये चारों पाद एक दूसरे से इस प्रकार जोड़े गए हैं कि जो अन्तिम सत्य की प्राप्ति कराते है।

भारतीय शिक्षा पद्धति इस विशिष्ट ज्ञान की महत्ता ई0पू0 5वीं शताब्दी में यूनान में भी दर्शमान होती है, जहाँ शारिरिक शिक्षा को विशिष्ट महत्व प्रदान करते हुए ''विकाररहित स्वस्थ शरीर'' की संकल्पना की गई है। क्योंकि ''स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास'' होता है।

योग शिक्षा का उद्देश्य है, मानव के मन, शरीर और इन्द्रियों का ऐसा सामंजस्यपूर्ण गंठबंधन जो उसे परम सत्य की अनुभूति के लिए तैयार कर सकें। महर्षि पंतजलि द्वारा उद्भूत इस महान विद्या का प्रयोग जनमानस को न केवल शारिरिक अपितु मानसिक स्तर पर उच्चता की अनुभूति कराते हुए उसे ज्ञान की पराकाष्ठा के मार्ग पर अग्रसर करता है।

नई शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत भारतीय मनीषा के इस अद्भुत रत्न को शिक्षा पद्धति में उचित रीति से शामिल करते हुए हम एक नए भारत की सृष्टि की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जो प्राच्य विश्व गुरू भारत को पुनः

वैश्विक नेतृत्व के सोपान की ओर ले जा सकता है। योग शिक्षा की महत्ता का आनुभाविक सूत्र हमें विष्णु पुराण के इस मंत्र में भी मिलता है–

" तत्कर्म यत्र बन्धाय, सा विद्या या विमुक्तये।
आयासयापंर कर्म, विद्यान्या शिल्प नेपुणम्।।

अर्थात कर्म वही है जो मुक्ति का साधक हो, और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो, इसके अतिरिक्त अन्य कर्म तथा विद्यायें तो कला कौशल मात्र हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा का क्रियान्वयन एवं चुनौतियां

सुनील कुमार भट्ट
शोध छात्र (शिक्षा संकाय)
कुमाँऊ विश्वविद्यालय अल्मोड़ा परिसर

सारांश

बालक के सर्वांगीण विकास में मातृभाषा के महत्व को देखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थापित करने की पुरजोर वकालत करती है। प्रस्तुत अध्ययन "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा का क्रियान्वयन एवं चुनौतियां" का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा हिंदी की धरातलीय स्थिति एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मातृ भाषा के क्रियान्वयन में संभावित समस्याओं का अध्ययन करना था। परिणाम दर्शाते हैं कि समाज में मातृ भाषा आधारित विद्यालयों के प्रति समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। शिक्षा माध्यम के रूप में हिंदी माध्यम विद्यालयों की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है जबकि पूर्व में गठित तमाम आयोगों की संस्तुतियों एवं नीतियों में मातृ भाषा को ही शिक्षा माध्यम के रूप में अपनाने की बात की गई है। दोषपूर्ण नीतिगत क्रियान्वयन के कारण मातृ भाषा आधारित शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः स्थापित नहीं हो पाई है। कोई भी नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसका क्रियान्वयन पूर्ण निष्ठा के साथ न किया जाए। अतः मातृभाषा को प्रोत्साहित करने हेतु सुचारु नीतिगत क्रियान्वयन की गहरी आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा आधारित शिक्षा के विचार को पूर्ण निष्ठा के साथ क्रियान्वित किया जाए। शिक्षक, शिक्षाविद, योजना निर्माता, नेता तथा समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति दोहरे चरित्र को त्याग कर स्वयं भी अपने पाल्यों की शिक्षा हेतु मातृभाषा माध्यम विद्यालयों का चयन करें।

मुख्य पद – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मातृभाषा , शिक्षा माध्यम, मातृभाषा का क्रियान्वयन, चुनौतियां